

पी.एम. सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रायगढ़ का एक ग्राम बनेगा ‘सोलर मॉडल विलेज’

जिला स्तरीय चयन समिति ने शुरू की चयन प्रक्रिया, 10 सर्वाधिक आबादी वाले ग्रामों में अगले छह माह चलेगी प्रतिस्पर्धा

सौर संयंत्र स्थापना, जनजागरूकता, सामुदायिक भागीदारी और नवाचार पर तय होगा मॉडल विलेज का चयन

रायपुर । केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पी.एम. सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत रायगढ़ जिले में एक ग्राम को पूर्णतः सौर ऊर्जा आधारित सोलर मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। इस दिशा में जिला स्तरीय चयन समिति ने औपचारिक रूप से चयन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जिले के उन्हीं ग्रामों को प्रतिस्पर्धा में शामिल किया जाएगा, जिनकी जनसंख्या 5 हजार से अधिक है। चूंकि जिले में इस श्रेणी के ग्राम सीमित संख्या में हैं, इसलिए प्रशासन ने सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 ग्रामों का चयन कर उन्हें छह माह की प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया

कलेक्टर ने बैंकर्स और वेंडर्स को पीएम सूर्य घर, योजना के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

लक्ष्य को पूरा करने बैंकर्स और वेंडर्स अच्छा समन्वय से काम करें: कलेक्टर डॉ. कन्नौज

वेंडर्स अधिक संख्या में हितग्राहियों को पीएम सूर्य घर योजना का लाभ दिलाएं

0कलेक्टर ने बैंकर्स को हितग्राहियों के दस्तावेजों की कमी को चेकलिस्ट 0में देने और देरी नहीं करने के निर्देश दिए

सारंगढ़। कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में बैंकर्स और वेंडर्स के साथ संयुक्त बैठक किया। उन्होंने बैंकर्स और वेंडर्स को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हितग्राहियों को अधिक से अधिक संख्या में इस योजना का लाभ दिलाएं। साथ ही लक्ष्य को पूरा करने में बैंकर्स और वेंडर्स

वीर शहीदों को नमन, सशस्त्र सेना झंडा दिवस गरिमामय ढंग से मनाया गया

रायगढ़ । मातृभूमि की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों की स्मृति में तथा सेवारत और भूतपूर्व सैनिकों के सम्मान में आज जिले में सशस्त्र सेना झंडा दिवस गरिमामय वातावरण में मनाया गया।कलेक्टोरेट परिसर स्थित सृजन सभा कक्ष में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता एडीएम अपूर्व टोप्पो ने की।

कार्यक्रम का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के अमर शहीदों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इस अवसर पर एडीएम अपूर्व प्रियेश टोप्पो ने सैनिकों के अद्वितीय योगदान और उनके महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सेना परिवार से जुड़ाव बल का विषय है। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि वे सैनिकों का सम्मान बनाए रखें और उनके समर्पित योगदान को हमेशा याद रखें। एडीएम ने सैनिकों के सर्वांगीण सहयोग का भी आश्वासन दिया। नसीसी कमांडिंग ऑफिसर कर्नल प्रवीण तेवतिया ने सैनिकों के बलिदान को याद करते हुए समाज के सभी वर्गों से उनके

कबीरधाम जिला अस्पताल में मातृ–शिशु चिकित्सा सुविधाएं हुई सुदृढ़

लगातार बढ़ रही प्रसव संख्या, अवटूरबर में हुए सर्वाधिक 413 प्रसव

कबीरधाम जिला अस्पताल रात्रि प्रसव में पूरे प्रदेश में टॉप पर

पड़ोसी जिलों के साथ मध्यप्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से भी लोग प्रसव के लिए कर रहे कवर्धा जिला अस्पताल का चुनाव

कवर्धा जिला अस्पताल में गूंज रही बच्चों की किलकारी

कवर्धा। कवर्धा में लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं का उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के नेतृत्व में तीव्र गति से विस्तार हो जा रहा है। जिसका परिणाम है कि जिला अस्पताल में लगातार प्रसवों की संख्या में इजाफ़ हुआ है। लोगों का विश्वास भी जिला अस्पताल कवर्धा पर बढ़ा है, जिसका अनुमान इससे लगाया जाता है कि कवर्धा में



में शामिल करने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार को गति देने के लिए जिलों को निरंतर कार्य करने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर सौर ऊर्जा लक्ष्य को धरातल पर साकार किया जा सके। रायगढ़ जिले में केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार जिले में प्रतियोगिता के लिए चयनित 10 ग्राम ग्राम पंचायतों में घरघोड़ा विकासखंड का ग्राम

कुडुमकेला, तमनार विकासखंड का ग्राम तमनार, रायगढ़ विकासखंड का ग्राम खैरपुर, धरमजयगढ़ विकासखंड का ग्राम विजयनगर, तमनार विकासखंड का ग्राम तराईमाल, लैलुंगा विकासखंड का ग्राम गहनाझरिया, पुसौर विकासखंड का ग्राम गढ़मरिया, धरमजयगढ़ विकासखंड का ग्राम छाल, पुसौर विकासखंड का ग्राम सिसरिंगा, और पुसौर विकासखंड का ग्राम कोडातराई। इन्हीं ग्रामों में से एक ग्राम जिले का पहला सोलर मॉडल विलेज

बनेगा। जिले के सभी विकासखंड से ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। इन ग्रामों में अब अगले छह माह तक सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने, जनजागरूकता अभियान चलाने, घरेलू एवं सामुदायिक सौर संयंत्रों की स्थापना, तथा योजनाओं के लिए ग्रामीणों द्वारा किए जाने वाले आवेदनों की सतत समीक्षा की जाएगी। इस प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक चयनित ग्राम में आदर्श ग्राम समिति गठित की जा रही है, जिसमें सरपंच, सचिव, जनप्रतिनिधि, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक, डॉक्टर, कृषि विस्तार अधिकारी तथा संबंधित शासकीय अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल होंगे। यह समिति डोर-टू-डोर संपर्क कर ग्रामीणों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। साथ ही पी.एम. कुसुम योजना, जल जीवन मिशन के सोलर डुअल पंप, सोलर हाईमास्ट, सोलर स्ट्रीट लाइट तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा आधारित व्यवस्थाओं की जानकारी भी प्रदान करेगी। क्रेडा के सहायक अभियंता श्री विक्रम वर्मा ने बताया कि इस प्रतियोगिता के दौरान प्रत्येक ग्राम अपनी जरूरतों के अनुसार सामुदायिक सौर संयंत्रों के प्रस्ताव तैयार कर जिला स्तर पर प्रस्तुत किया जाएगा।

ग्राम सभा कोलियारी ने नशामुक्त ग्राम बनाने के लिए,सर्वसम्मति से लिया संकल्प

नगरी/दुगली । जिले के वनांचल क्षेत्र नगरी विकासखण्ड के ग्राम पंचायत कोलियारी के ग्राम सभा के सदस्यों ने ग्राम में नशा से बिराड़ते परिवेश को देखते हुए 1 दिसंबर दिन सोमवार को विशेष ग्राम सभा आहूत कर नशामुक्त ग्राम बनाने का सर्वसम्मति से संकल्प लेते हुए दंडात्मक कार्यवाही के लिए विशेष नियम कायदे बनाए। जिस प्रस्ताव को ग्राम वासियों ने पूर्ण रुप से समर्थन दिया।

अगर ग्रामसभा की कोई भी सदस्य या किसी परिवार व्दारा कच्ची शराब बनाते पाया गया तो उन्हें 50,000 का दंड लिया जावेगा। अगर ग्राम में शराब बेचते पाया गया तो उन्हें 60,000 का दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। अगर ग्राम में किसी व्यक्ति व्दारा सार्वजनिक या सामाजिक स्तर पर शराब पीने की स्थिति में मौजूद हैं या पुष्टि होता है तो 30,000 की दंडात्मक कार्यवाही से गुजरना पड़ेगा। और अगर किसी ग्रामीण के व्दारा उक्त अपराध की जानकारी ग्राम सभा को उपलब्ध कराता है तो उन्हें 25,000 की राशि से प्रोत्साहित भी किया जाएगा।यह संकल्प ग्राम पंचायत कोलियारी के विशेष ग्राम सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। उक्त जानकारी सरपंच ग्राम पंचायत कोलियारी मोनिका मंडावी,पूर्व सरपंच तुलसी राम मंडावी,उपसरपंच लोकेश कोराम ने दी। वहीं विशेष ग्राम सभा में ग्रामीण अध्यक्ष रामलाल तुमरेटी,उपाध्यक्ष भावसिंह कोराम,ग्राम पटेल जलसू राम कुंजाम,सोमर सिंह नेताम,चिंताराम नेताम, धनाजी कुंजाम,राधेलाल तुमरेटी,नवल सिंह वट्टी,सुद्धाराम मरकाम,ब्रजलाल तुमरेटी,सोमार राम कवाची,दयालराम मंडावी,राजेश नेताम,राजूराम मरकाम,शंभु टेकाम, गणेश तुमरेटी,राधाबाई तुमरेटी,रामबाई मंडावी,रोहणी बाई नेताम,राधाबाई नेताम,भक्तीन बाई कोमरे,रामबाई तुमरेटी,सहीत ग्राम सभा कोलियारी के सदस्य उपस्थित रहे।

प्रदेश में धान खरीदी का महाअभियान तेजी के साथ जारी, 22.25 लाख मीट्रिक टन

एमसीबी/खड़गवां । आज

जनपद पंचायत खड़गवां के रतनपुर में बहुप्रतीक्षित अंजनी जलाशय योजना के नहर विस्तारीकरण एवं सीसी चैनल निर्माण कार्य का भूमि पूजन स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। लगभग 426.40 करोड़ रुपये की लागत से इस महत्वपूर्ण परियोजना की शुरुआत की गई है।

कार्यक्रम में जनपद पंचायत खड़वां की अध्यक्ष श्याम बाई मरकाम, उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह करियांम, निरमिरी नगर पालिक निगम के मेयर राम नरेश राय, रतनपुर के सरपंच नरेंद्र कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, ग्रामीण, जल संसाधन विभाग के अधिकारी

एवं ठेकेदार उपस्थित रहे।

नहर विस्तारीकरण से रतनपुर की 75व भूमि होगी सिंचित

जल संसाधन विभाग के ए. टोप्पो ने बताया कि अंजनी जलाशय योजना के तहत नहर का निर्माण तो पूर्व में हो चुका था, लेकिन नहर अपने मूल उद्देश्य के अनुरूप जल आपूर्ति नहीं कर पा रही थी। अब नहर को पूरी तरह पक्की (सीसी चैनल) किया जा रहा है, जिससे अधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। रतनपुर ग्राम पंचायत की लगभग 75 प्रतिशत भूमि सिंचित होगी, वहीं नए नहर मार्ग से छूटे क्षेत्रों को भी शामिल करने की योजना है।

यह परियोजना क्षेत्र का ‘भाग्योदय’ – स्वास्थ्य मंत्री मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री

श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि छत्तीसगढ़ का हर किसान साल में दो बार खेती कर सके। इसी उद्देश्य के तहत अंजनी जलाशय योजना के नहर विस्तारीकरण के लिए स्वीकृति दी गई है और आज इसका शुभारंभ किया गया है।उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूर्ण होने पर रतनपुर की अधिकांश भूमि सिंचित होगी तथा शेष 25 प्रतिशत के लिए भी योजनाएँ तैयार हैं।

मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय कई कार्य रोक दिए गए थे, जिससे आम जनता प्रभावित हुई। अब भाजपा सरकार में वे सभी रुके हुए कार्य शुरू किए जा रहे हैं जिनकी जनता को वर्षों से आवश्यकता थी।

कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे ने पोस्ट मैट्रिक कन्या, छात्रावास का किया आकस्मिक निरीक्षण

कलेक्टर ने वहां के रसोई और परिसर के साफसफाई, बच्चों के लिए मच्छरदानी, प्रकाश व्यवस्था का जायजा लिया

सारंगढ़ बिलाईगढ़। कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे ने सारंगढ़ स्थित पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान आदिम जाति विकास विभाग के सहायक आयुक्त बद्रीश सुखदेवे भी साथ में थे। कलेक्टर ने वहां के रसोई और परिसर के साफ सफाई, बच्चों के लिए मच्छरदानी, प्रकाश व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही बच्चों से पढ़ाई के बारे में बातचीत किया। बालिकाओं से कलेक्टर ने आगामी परीक्षा की तैयारी के संबंध में क्या रणनीति बनाएं इसकी जानकारी लेते हुए उनके कोर्स के बारे में पूछताछ किया। बालिकाओं ने अपनी

तैयारी के संबंध में जानकारी दी। कलेक्टर ने बच्चों को दिए जाने वाले नाश्ता और भोजन की क्वालिटी, स्वाद के संबंध जानकारी लिया। इसके साथ ही डॉक्टर के द्वारा रूटीन चेकअप की भी जानकारी लिया। उन्होंने हीमोग्लोबिन और सिकलिन जांच करने के लिए भी बालिकाओं को प्रोत्साहित किया। कलेक्टर ने सहायक आयुक्त बद्रीश सुखदेवे को निर्देश दिया कि बालिकाओं को सभी विभागीय सुविधा हमेशा प्रदान करने रहे।कलेक्टर के निर्देश पर, हरदी छात्रावास में बच्चों को मिला खेल सामग्रीकलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे के द्वारा विगत रविवार को हरदी के छात्रावास का निरीक्षण करने पर वहां खेल सामग्री की बच्चों ने मांग किया था, जिस पर कलेक्टर के निर्देश पर बच्चों को खेल सामग्री उपलब्ध कराया गया है।

आश्रम, छात्रावास में अधीक्षक अपने जिम्मेदारी का,अच्छे से पालन करें नहीं तो होगी कार्रवाई : कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे



सारंगढ़-बिलाईगढ़ । जिलाधीश डॉ संजय कन्नौजे ने कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में जिले के आश्रम, छात्रावास के अधीक्षक और अधीक्षकाओं का जिला स्तरीय समीक्षा बैठक लिया। यह बैठक आश्रम छात्रावास में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए किया गया था। कलेक्टर डॉ कन्नौजे ने सभी अधीक्षक और अधीक्षकाओं से परिचय के साथ, उनकी पदस्थापना, कब से पदस्थापना, कितने सीटर का आश्रम छात्रावास, कन्या छात्रावास में होमागार्ड की पोस्टिंग और उपस्थिति, कितने बच्चे दाखिल, कोई परेशानी, कमी या मांग की जानकारी लिया। बैठक में बेहतर देखरेख, अच्छ नाश्ता, भोजन, खानपान के लिए छिंद और भटगांव के छात्रावास तथा बेहतर किचन गार्डन के लिए उलखर छात्रावास के कार्यों की तारीफ कलेक्टर ने किया। इस अवसर पर सभी ने तालियां से हौसला अपन्नाई की। कलेक्टर ने छह माह पहले के बैठक में दिए निर्देश के पालन में किये गए कार्यों और स्वीकृत भवन मरम्मत, नवीन निर्माण की स्थिति की जानकारी लिया। बैठक में सहायक आयुक्त आदिम जाति विकास, बद्रीश सुखदेवे डिप्टी कलेक्टर शिक्षा शर्मा, डॉक्टरसं, मंडल संयोजक, सभी अधीक्षक और अधीक्षका उपस्थित थीं।कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे ने कहा कि, आश्रम, छात्रावास में अधीक्षक और अधीक्षकाओं को पालक की भांति बच्चों की देखरेख, पूछ परख करनी चाहिए। घर से दूर घर जैसा माहौल देना चाहिए ताकि छुट्टी के बाद भी उनका आश्रम छात्रावास में लौटने का मन हो। उनके साथ ऐसा व्यवहार माहौल बना के रखना चाहिए जिससे वह अपनी सभी बातें बता सके। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ-साथ नैतिक ज्ञान, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम करियर गाइडन्स आदि गतिविधियां बीच-बीच में करते रहने चाहिए। नारा +बाकी दिन शिक्षक का एक दिन अधीक्षक का+ तर्ज पर सप्ताह में अवकाश पर इस प्रकार की गतिविधियों का आयोजन छात्रावास आश्रम में किया जाना चाहिए। सभी बच्चों का व्यक्तिगत रूप से नाम, पालक का नाम, पता, काटेक्ट नंबर आदि की जानकारी रिकॉर्ड में और व्यक्तिगत रूप से भी होनी चाहिए। जैसे छुट्टी जा रहे हैं तो किस कारण से जा रहे हैं और कब लौटेंगे। सभी बच्चे शेड्यूल समय में उपस्थित रहे। खाने नाश्ता भोजन आदि की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए और प्रत्येक दिनों के लिए अलग-अलग किस्म के नाश्ते और सब्जी में परिवर्तन किया जाना चाहिए ताकि वह सभी प्रकार के विटामिन बच्चों को मिले। आश्रम छात्रावास के भवन, खिड़की, दरवाजा, टेबल, लाइट, पेयजल, शौचालय आदि के टूट-पूट मरम्मत के छोटे-छोटे काम के लिए बड़ई, मिस्त्री से काम काएं। इसके लिए अनावश्यक देरी न करें। जितने आश्रम छात्रावास खेत के पास हैं उनके खिड़की दरवाजा में जाली लगाएं ताकि सांप, बिच्छू प्रवेश न करें। सभी खिड़की दरवाजा में पर्दा लगाएं। कमरों में पर्याप्त रोशनी हो। सभी बच्चों को मच्छरदानी मिले। अधीक्षक हॉस्टल में रहे, यदि वे अनुपस्थित रहेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने कहा, आश्रम छात्रावास परिसर, किचन,

परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने आईडीटीआर का किया निरीक्षण

रायपुर । परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने आज नवा रायपुर स्थित आईडीटीआर (इंस्टीट्यूट ऑफ़ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च) तेंदुआ का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान परिवहन सचिव एस. प्रकाश, संयुक्त परिवहन आयुक्त यू.बी.एस. चौहान और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मंत्री कश्यप को आईडीटीआर के संचालन, प्रशिक्षण व्यवस्था, ऑटोमोबाइल लैब और वाहन सिमुलेटर के माध्यम से दिए जा रहे प्रशिक्षण की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने क्लासरूम एवं लैब प्रशिक्षण के साथ ही ड्राइविंग ई-ट्रैक में चालकों के कौशल परीक्षण की प्रक्रिया का भी अवलोकन कराया। इस दौरान मोटरसाइकिल और भारी वाहनों के माध्यम से ड्राइविंग टेस्ट का प्रदर्शन किया गया।



मंत्री कश्यप ने राज्य के विभिन्न जिलों से प्रशिक्षण के लिए आए वाहन चालकों से चर्चा की। चालकों ने बताया कि यहां उन्हें वाहन संचालन के साथ-साथ बुनियादी तकनीकी ज्ञान, ड्राइविंग कौशल में सुधार और मोटररयान अधिनियम एवं

नियमों की महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है। मंत्री ने परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया कि रायपुर और आसपास के जिलों के अधिक से अधिक वाहन चालकों को प्रशिक्षण और रिफ्रेश कोर्स के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने

कहा कि मोटररयान अधिनियम के उल्लंघन के कारण जिन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जा रहे हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से आईडीटीआर में प्रशिक्षण दिलाया जाए, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। इसके साथ ही कश्यप ने स्कूल

बस चालकों के नियमित प्रशिक्षण और रिफ्रेश कोर्स को अनिवार्य रूप से निरंतर संचालित करने के निर्देश दिए।

मंत्री कश्यप ने आगे कहा कि राज्य शासन के विभिन्न विभागों में ड्राइवर भर्ती प्रक्रिया के दौरान ड्राइविंग परीक्षण आईडीटीआर के माध्यम से कराए जाएं, ताकि उपलब्ध अत्याधुनिक सुविधाओं का उपयोग करते हुए कुशल वाहन चालकों का चयन सुनिश्चित किया जा सके।

स्कूल शिक्षा विभाग में लिपिक वर्गीय पदोन्नति के लिए कार्यवाही विषयक जापन रायपुर, 07 दिसंबर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ राज्य मे स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत प्राचार्य /व्याख्याता/प्रधानपाठक की पदोन्नति व्यापक स्तर पर किया गया है परन्तु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग के रिक्त पद वरिष्ठ लेखा परीक्षक एवं सहायक

ग्रेड-एक के पद पर विगत कई वर्षों से पद रिक्त होने के बावजूद भी अभी तक पदोन्नति की कार्यवाही नही किया गया है।

नवा रायपुर दिनांक जनवरी 31/12/24 द्वारा पदोन्नति हेतु निर्देश भी जारी किया गया है परन्तु लिपिको का दुर्भाग्य है कि अभी तक पदोन्नति के संबंध मे कोई कार्यवाही नही किया गया है जिससे लिपिक वर्गीय संघ एवं लिपिको में अत्यन्त रोष व्याप्त है, जिसके कारण लिपिको मे अन्य संवर्ग एवं लिपिक संवर्ग मे भेदभाव परिलक्षित हो रही है। तदसंबंध मे शासन के उपरोक्त निर्देशानुसार रिक्त पद पर पदोन्नति की कार्यवाही हेतु छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ जिला शाखा अध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन मीडिया प्रभारी-दुर्ग भानुप्रताप यादव द्वारा कलेक्टर महोदय दुर्ग को पत्र प्रेषित किया गया है।

बैंगलोर में सांसद बृजमोहन अग्रवाल का भव्य समाजसेवा व शिक्षा सुधार पर दिए दूरदर्शी

अग्रवाल समाज ने किया सांसद बृजमोहन का सम्मान, गरीबों की शिक्षा, स्वास्थ्य व भविष्य निर्माण पर जोर

बैंगलोर रायपुर । प्रवास के दौरान रायपुर लोकसभा के लोकप्रिय सांसद, दूरदर्शी नेता और समाजसेवा के लिए समर्पित बृजमोहन अग्रवाल का रविवार को बैंगलोर में अग्रवाल समाज विकास ट्रस्ट, अग्रवाल समाज कर्नाटक तथा फ़उंडेशन इंडिया ने संयुक्त रूप से आयोजित विशेष समारोह में अत्यंत भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। समाज के गणमान्य सदस्यों ने गर्मजोशी के साथ उनका अभिनंदन करते हुए उन्हें जनसेवा में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए धन्यवाद दिया।अपने प्रभावशाली उद्बोधन में सांसद अग्रवाल ने समाज के बौद्धिक वर्ग, उद्योगपतियों, शिक्षाविदों और युवा नेतृत्व से अत्यंत संवेदनशील और दूरगामी संदेश साझा किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि समाज तभी महान बनाता है जब वह अपने कमजोर वर्गों, जरूरतमंद परिवारों और प्रतिभाशाली संसाधनविहीन बच्चों को आगे बढ़ाने का संकल्प ले।सांसद

अग्रवाल ने कहा कि, भगवान महाराजा अग्रसेन जी के एक ईंट ड़ु एक रुपया के पुण्य मंत्र ने सदियों से समाजसेवा की वह अतुलनीय परंपरा गढ़ी है, जो आज भी हमारी सामूहिक शक्ति और परोपकार की पहचान है।उन्होंने गरीब बेटियों की शादी, निर्धन परिवारों के इलाज और जरूरतमंद छात्रों की शिक्षा समाज के इन पवित्र कार्यों के माध्यम से समाज को एकजुट और मजबूत बनाने का आह्वान किया।उन्होंने समाज से विशेष आग्रह किया कि, समाज द्वारामेंडकल, लॉ, सिविल सर्विसेज व अन्य उच्च शिक्षा हेतु उत्कृष्ट कोचिंग केंद्र प्रारंभ किए जाएँ।छात्र-छात्राओं एवं वर्किंग वूमन के लिए आधुनिक हॉस्टल की व्यवस्था की जाए ताकि सुखा और सुविधा के साथ युवा आगे बढ़ सकें।उन्होंने कहा कि, गरीब बस्तियों, रेलवे पटरी किनारे बसे परिवारों तथा कमजोर वर्गों का सर्वे कर उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बेहतर जीवन हेतु ठोस कार्ययोजना बनाई जाए।उन्होंने कहा कि समाज केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन हजारों परिवारों के लिए कार्य करे जो आज भी बेहतर अवसरों से वंचित हैं।

वीर सैनिकों के कारण ही हमारा जीवन और संपत्ति सुरक्षित है – राज्यपाल डेका

सशस्त्र सेना झण्डा दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में हुए शामिल राज्यपाल

रायपुर। सशस्त्र सेना झण्डा दिवस के अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य में लोकभवन के छत्तीसगढ़ मण्डपम में गौरवपूर्ण समारोह आयोजित किया गया। राज्यपाल रमेन डेका ने इस अवसर पर कहा कि सैनिक निस्वार्थ भाव से हमेशा देश की रक्षा के लिए तैयार रहते है और अपना जीवन देश सेवा के लिए लगाते है। उनके कारण ही हमारा जीवन और संपत्ति सुरक्षित है। इस अवसर पर राज्यपाल ने सशस्त्र झण्डा दिवस निधि के लिए 2 लाख रूपए की सहयोग राशि राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड को प्रदान की।कार्यक्रम में राज्यपाल ने सभी शहीदों की वीर नारियों एवं माताओं, आश्रितों को सम्मान राशि और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। वीरता अलंकरण प्राप्त सैनिकों और झण्डा दिवस के अवसर पर विशेष योगदान देने वाले दानदाताओं का सम्मान भी किया। राज्यपाल श्री डेका ने अपने उद्बोधन के दौरान इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि झण्डा

दिवस निधि से लगभग 27 महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है जिनके माध्यम से पूर्व सैनिकों और आश्रित परिवारों को निरंतर सहायता मिल रही है। छत्तीसगढ़ सैनिक कल्याण बोर्ड और गृह विभाग के सहयोग से हमारे वेटरन्स की उत्कृष्ट देखभाल सुनिश्चित की जा रही है। डेका ने कहा कि हमारे सैनिक कठिन परिस्थितियों में अपना कार्य करते हैं। माइनस डिग्री के तापमान में भी अपनी जिम्मेदारी कुशलता से निभाते है। उन्होंने शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को नमन किया और कहा कि आप लोगों का त्याग अमूल्य है। लोकभवन और छत्तीसगढ़ सरकार आपके साथ मजबूती से खड़े हैं। सेवारत एवं सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए हम निरंतर प्रतिबद्ध है। समारोह की शुरुआत में शहीद सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित की गई और दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सशस्त्र सेना झण्डा दिवस का प्रतीक बैज लगाकर श्री डेका को सम्मानित किया गया। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कैप्टन अनिल कुमार शर्मा ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मु के संदेश का वाचन किया।

छत्तीसगढ़ के स्कूलों में फिर एक बार लागू होगा सहायक वाचन, इतिहास और संस्कृति पढ़ेंगे छात्र

एसईआरटीसी और साक्षरता मिशन को सहायक वाचन की किताब तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई

रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में एक बार फिर सहायक वाचन लागू होने वाला है। इसे नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू किया जाएगा। प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने इसे दोबारा लागू करने के लिए जरूरी निर्देश दिए है। वहीं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एसईआरटीसी) और साक्षरता मिशन को सहायक वाचन की किताब तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। सहायक वाचन से क्या होगा फ़ायदा? स्कूलों में सहायक वाचन लागू होने से कक्षा तीसरी से आठवीं तक के स्कूली छात्र देश-प्रदेश के इतिहास, संस्कृति, परंपराओं, कला, नदियों और विरासत के बारे में सरलता और गहराई से पढ़ सकेंगे। इसकी किताबों में क्रांतिकारी, शहीदों, स्वतंत्रता



संग्राम सेनानियों और महापुरुषों की जीवन गाथाएं विशेष रूप से शामिल होंगी। जिससे बच्चों को राष्ट्र और समाज निर्माण में उनके योगदान की जानकारी मिल सके।

नई व्यवस्था के लिए काम शुरू छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में सहायक वाचन को पुनः लागू करने के निर्देश

दिए थे। इसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और बच्चों को अपने प्रदेश तथा देश के गौरवपूर्ण इतिहास से परिचित कराना है। मंत्री के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लेखन और सामग्री निर्माण का काम शुरू कर दिया है।

पुस्तकों में क्या-क्या होगा शामिल? अधिकारियों के अनुसार, सहायक वाचन की नई पुस्तकों में छात्रों की उम्र के अनुसार सरल भाषा, प्रेक प्रसंग और शिक्षाप्रद घटनाओं को शामिल किया जाएगा। जिससे बच्चों में पढ़ने की आदत मजबूत हो और उनमें अपने प्रदेश तथा राष्ट्र के प्रति समझ और जुड़ाव बढ़े। विभाग का मानना है कि इस पहल से न सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि नई पीढ़ी अपने इतिहास और सांस्कृतिक पहचान को भी अधिक गहराई से समझ सकेंगे। तैयारी तेज गति से चल रही है और समय पर इसे लागू करने का लक्ष्य रखा गया है।

14.60 लाख की ‘लूट’ की कहानी निकली फर्जी

दुर्ग । जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र के कपसदा गांव में कथित रूप से हुई 14 लाख 60 हजार रुपये की लूट का मामला पूरी तरह फर्जी निकला है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि कोई लूट नहीं हुई थी, बल्कि यह पूरी कहानी खुद शिकायतकर्ता और हिताची कंपनी के कैशियर ने गढ़ी थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।बता दें कि बीते शनिवार देर रात कैशियर आशीष राठौर ने कुम्हारी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि वह हिताची कंपनी के एटीएम में रकम डालने 14 लाख 60 हजार रुपये लेकर कपसदा जा रहा था। रास्ते में तीन अज्ञात युवक बाइक से आए और चाकू दिखाकर उससे रकम लूटकर फ़ार हो गए। शिकायत के बाद मामला गंभीर होने पर कुम्हारी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।पुलिस टीम ने घटनास्थल और आसपास के इलाके में लगे छद्मचक्र कैमरों की फुटेज खंगाली, स्थानीय लोगों से पूछताछ की।

शिक्षा ही सामाजिक विकास का मूलमंत्र : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

मुख्यमंत्री साय सर्व रविदास समाज के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल

रायपुर। सामाजिक विकास का वास्तविक आधार शिक्षा है। चाहे जीवन जीने की कला हो, व्यापार हो, कृषि हो या कोई अन्य क्षेत्र हर क्षेत्र में सफलता का पहला कदम शिक्षा ही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषक सभागार में आयोजित छत्तीसगढ़ प्रदेश सर्व रविदास समाज के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री साय ने मंच पर सभी नव-निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और उन्हें शुभकामनाएं दीं।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार प्रारंभ से ही शिक्षा के स्तर को उन्नत करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। राज्य गठन के समय जहाँ मात्र एक मेडिकल कॉलेज था, वहीं आज प्रदेश में लगभग 15 मेडिकल कॉलेज संचालित हो



रहे हैं। इसी प्रकार, छत्तीसगढ़ में आईआईटी, टिपल-आईटी, आईआईएम, लॉ यूनिवर्सिटी, एम्स, सिपेट जैसे राष्ट्रीय एवं

समाज को मजबूत और संगठित होना समय की आवश्यकता है, क्योंकि संगठित समाज ही राष्ट्र निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मूलमंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का उल्लेख करते हुए कहा कि इन्हीं मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार राज्य सरकार 23 महीनों से सभी वर्गों के हित में काम कर रही है।मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हाल के महीनों में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जिसमें अन्नदाताओं के लिए कृषक उन्नति योजना, प्रत्येक परिवार को पक्का मकान देने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना, माताओं और बहनों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने वाली महतारी वंदन योजना, दूरस्थ अंचलों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु शिक्षक युक्तियुक्तकरण जैसे कदम शामिल हैं।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अब तक विभिन्न विभागों में 10 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र

प्रदान किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं पूर्ण निष्पक्षता के साथ संपन्न कराई गई हैं, जिससे युवाओं में नया विश्वास उत्पन्न हुआ है।उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने नई उद्योग नीति लागू की है, जिससे स्थानीय लोगों को अधिक अवसर, रोजगार और स्वरोजगार प्राप्त हो सकेगा।मुख्यमंत्री साय ने समाज के लोगों से आग्रह किया कि वे धिकाधिक संख्या में शासन की योजनाओं का लाभ लेकर अपने जीवन में परिवर्तन लाएँ।कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड के अध्यक्ष ध्रुव कुमार मिर्धा ने भी संबोधित किया और नव-निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी।इस अवसर पर सर्व रविदास समाज के प्रदेश अध्यक्ष विजय मेहरा, रायपुर संभाग आयुक्त महादेव कांवरे, दिलीप वासनीकर सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ में 18 को आयोजित होगी डाक अदालत, ग्राहकों की शिकायतों पर होगा प्रत्यक्ष समाधान



रायपुर । डाक सेवाओं से संबंधित शिकायतों का त्वरित और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कार्यालय मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, छत्तीसगढ़ परिमण्डल, रायपुर द्वारा परिमण्डल स्तर पर डाक अदालत आयोजित की जाएगी। यह अदालत 18 दिसम्बर 2025 (गुरुवार) को शाम 4.00 बजे प्रत्यक्ष एवं वर्चुअल दोनों माध्यमों से आयोजित की जाएगी।

डाक अदालत में डाक ग्राहकों की विभिन्न श्रेणियों की शिकायतों—जैसे डाक वस्तुओं

का वितरण, काउंटर सेवाएँ, लघु बचत योजनाएँ (आर.डी., बचत बैंक, बचत पत्र आदि), रजिस्ट्री, वी.पी. पार्सल, एक्सप्रेस पार्सल, स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर, डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा—का समाधान प्राथमिकता के साथ किया जाएगा।ग्राहकों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी शिकायतें, यदि कोई हों, तो संबंधित प्रकरण का पूर्ण विवरण सहित 16 दिसम्बर 2025 को दोपहर 2.00 बजे तक कार्यालय मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, छत्तीसगढ़ परिमण्डल, रायपुर में प्रस्तुत करें।

कृषकों के लिए उन्नति का नया द्वार : समर्थन मूल्य एवं कृषक उन्नति योजना से किसान हो रहे सशक्त

किसान गोपाल ने धान बिक्री से भूमि विस्तार के बाद अब घर निर्माण का बनाया लक्ष्य

रायपुर । राज्य शासन द्वारा किसानों की उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई समर्थन मूल्य नीति एवं कृषक उन्नति योजना किसानों के जीवन में परिवर्तन का कारण बन रही है। प्रति क्विंटल 3100 रुपए की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी का निर्णय किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहा है। पारदर्शी खरीदी प्रक्रिया और उपार्जन केन्द्रों में उपलब्ध बेहतर सुविधाओं से राज्य के सभी जिले के कृषक अत्यंत संतुष्ट हैं।

किसान गोपाल बने प्रगतिशील कृषि का उदाहरण : राजनांदागांव विकासखंड के धान उपार्जन केन्द्र मनकी में ग्राम सुंदरा निवासी किसान गोपाल प्रसाद ने गत दिवस अपने दूसरे



ऑनलाइन टोकन के माध्यम से 71 क्विंटल धान का विक्रय किया। उन्होंने बताया कि समर्थन मूल्य एवं कृषक उन्नति योजना ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं। समय पर खाद-बीज उपलब्ध होने और

सुविधाजनक प्रक्रियाओं के कारण उनकी 18 एकड़ कृषि भूमि से उत्कृष्ट उत्पादन प्राप्त हुआ। गोपाल ने बताया कि पिछले वर्ष धान विक्रय से मिली राशि से उन्होंने अपनी कृषि भूमि का विस्तार किया था। इस वर्ष प्राप्त होने वाली धान बिक्री राशि

से वे नया घर निर्माण करने की योजना बना रहे हैं। उनका कहना है कि शासन की नीतियों के चलते किसानों की आय में वृद्धि हो रही है और जीवन स्तर में महत्वपूर्ण सुधार आया है। ऑनलाइन टोकन प्रणाली बनी

संपादकीय

जीडीपी में बढ़तेरी सफलता का प्रतीक

इस बार नोमिनल जीडीपी 8.07 प्रतिशत दर्ज हुई। सरकार ने इससे 0.5 प्रतिशत मुद्रास्फीति दर को घटया, इसलिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 8.2 फीसदी बताई गई है। मगर दूसरी तिमाही में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दर 1.9 प्रतिशत थी। पहले के चलन के तहत अगर नोमिनल दर को इससे डिफ्लेट किया जाता, तो जीडीपी वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत नजर



मां सरस्वती का आशीर्वाद

मां सरस्वती का आशीष, ज्ञान का उजियारा , अज्ञान के अंधकार में, दीप ज्ञान का प्यारा ।

ज्ञान धन अनमोल,कोई इसे ले न जाए

लाख पहरे बैठा दो,कोई इसे चुरा न पाए।

न सोने की मीनारें चाहें, न कोई रखवाला

ज्ञान को सुरक्षा की चाहत नहीं,

फैलाये ज्ञान का उजियारा घ

कंचन-रत्नों से कीमती, अक्षर का यह भंडार जिससे जगमग हर कोना,ज्ञान प्रकाश से हो भरमार ।

दुनिया की हर सीमा टूटे, जब शब्दों की गंगोत्री बहे, मानवता का संदेश लिए, शिक्षा की जमनीत्री चले।

मां वीणा की तारों से, रागिनी प्रज्ञा की झरती ,य हर हृदय जहां सरस्वती, वहाँ सत्य स्वर माला उभरती ।

ज्ञान की ज्योति जलती , सदियों तक समता भर दे, युगों-युगों तक मानवता को, सन्मार्ग का पथ प्रदर्शन कर दे।

ज्ञान अमर , अक्षर अमर, अमिट प्रकाश उभरता , मां सरस्वती का वंदन कर, जीवन सफल सँवरता ।

– संजीव ठाकुर

PM: 2024 -
Vishwa Sarkar Ka Vikalp

Modimaya
Vaidik Netriiva

Rashtriya Ekta

DLF-Vadra-
Bhrasht Tantra

Silent Assassins
Jan11,1966

Accursed & Jihadi
Neighbour

QR CODE SCAN
कर प्रेमेन्द्र अग्रवाल द्वारा
लिखित पुस्तकें पढ़िये
ऑनलाईन

ताइवान को दूसरा यूक्रेन बनाने की अमेरिकी तैयारी और भारतीय दृष्टिकोण की अहमियत ।

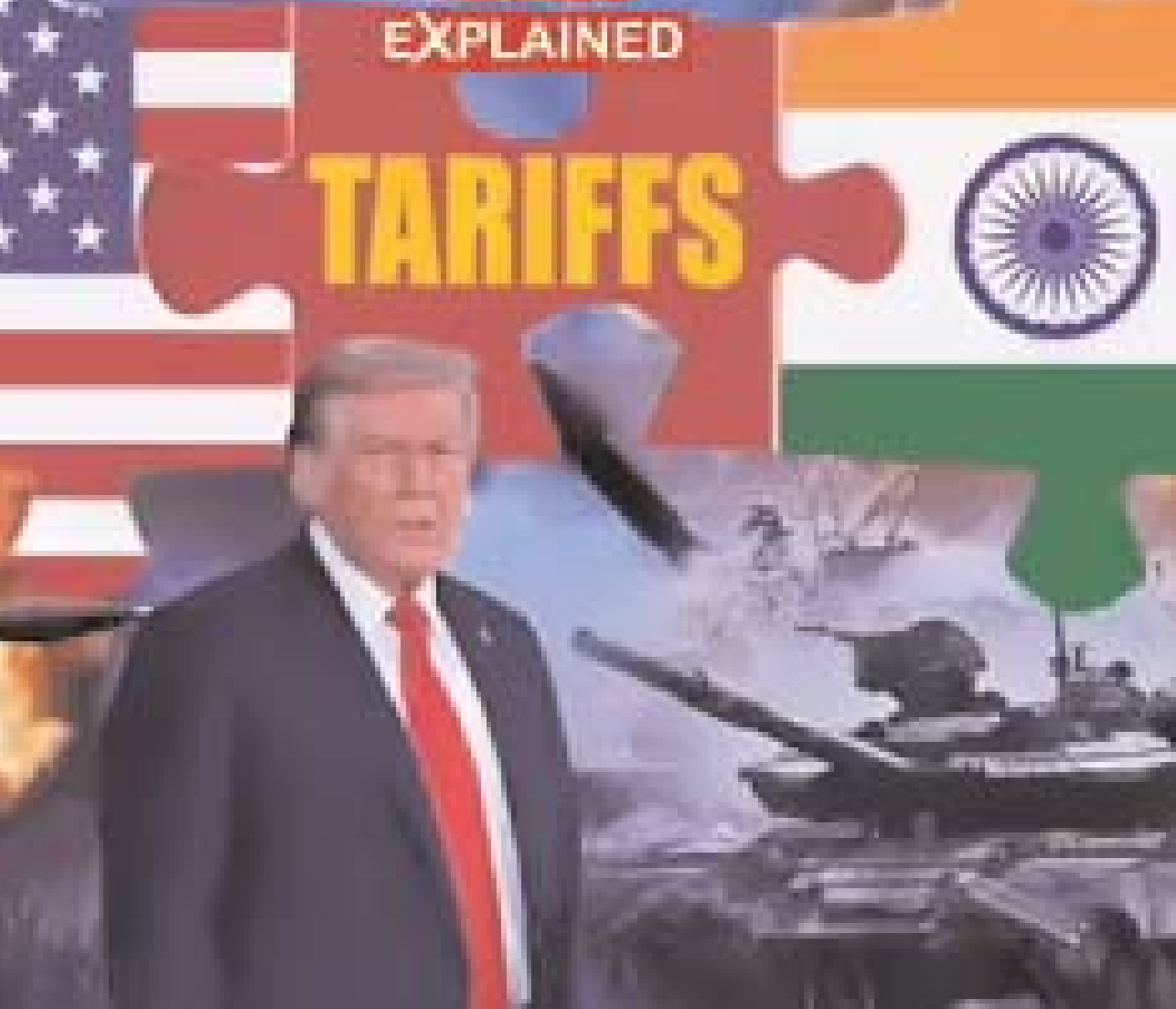
दुनिया आज एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहाँ वैश्विक शक्ति-संतुलन तेजी से बदल रहा है, और इसी शक्ति संघर्ष के केंद्र में ताइवान खड़ा है, जिसे अमेरिका और चीन के बीच तनाव की धुरी माना जाने लगा है। रूस-यूक्रेन युद्ध ने विश्व को यह दिखा दिया है कि महाशक्तियों के भू-राजनीतिक खेल में छोटे देश किस तरह तबाह हो जाते हैं, और अब यही खतरा ताइवान के सिर पर मंडरा रहा है। अमेरिका द्वारा ताइवान को लगातार सैन्य, राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है, ठीक उसी तरह जैसे यूक्रेन को रूस के विरुद्ध भड़काया गया था। इतिहास गवाह है कि अमेरिका जिस देश का समर्थन करता है, वह अंततः संकट की कगार पर पहुंच जाता है। डूट्सअफ़ानिस्तान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहाँ तालिबानी आतंकवाद के खिलाफनिर्णायक संघर्ष के समय अमेरिका ने रातों-रात सेना वापस बुलाकर अफ़ानिस्तान को अराजकता और ख़ुनी सत्ता-परिवर्तन के हवाले कर दिया। यूक्रेन को रूस के विरुद्ध खड़ा करने का परिणाम दुनिया देख चुकी है-अरबों का नुकसान, लाखों निर्दोष लोगों की मौतें, शहरों का मलबा, और युद्ध का अंत आज तक नहीं। अमेरिका और नाटो के राष्ट्र बाहर बैठकर तमाशबीन बने रहे, हथियार बेचे, राजनीति चमकाई, पर जमीन पर कोई निर्णायक समर्थन नहीं दिया। अब ताइवान पर यही खेल दोहराया जा रहा है।

अमेरिका द्वारा ताइवान की संप्रभुता जैसी संवेदनशील विषय पर खुला समर्थन, ारणनीतिक अस्पष्टता+ की नीति के बजाय स्पष्ट हस्तक्षेप का संकेत देता है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैसी पेलोसी की ताइवान यात्रा, चीन की कड़ी चेतावनियों के बावजूद, अमेरिका की उस रणनीति को दर्शाती है जो चीन-विरोधी शक्ति संतुलन बनाने के लिए ताइवान को मोहरें की तरह इस्तेमाल कर रही है। चीन ने इस यात्रा को अपनी संप्रभुता में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बताया और सैन्य कार्रवाई की खुली धमकी दी, उसकी सेना ने ताइवान के चारों ओर लाइव-फ़ायर सैन्य अभ्यास का ऐलान करते हुए युद्ध-स्तरीय तैयारी शुरू कर दी। नैसी पेलोसी ने ताइवान पहुंचकर कहा कि 23 मिलियन ताइवानी लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की है। ऐसे बयान यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से पहले अमेरिका द्वारा दिए गए बयानों जैसे ही प्रतीत होते हैं, जहाँ यूक्रेन को ापूर्ण समर्थन+ का आश्वासन दिया गया, पर युद्ध शुरू होते ही अमेरिका ने सुरक्षित दूरी बना ली।

चीन 20 वर्ष पहले वाला देश नहीं। सैन्य, आर्थिक और सामरिक क्षमता में वह विश्व की शीर्ष तीन शक्तियों में है। रूस-यूक्रेन युद्ध में उसने रूस का समर्थन कर यह संकेत दिया कि वह पश्चिमी गठबंधन को चुनौती देने के लिए तैयार है। यदि चीन और अमेरिका के बीच ताइवान विवाद खुली लड़ाई में बदलता है, तो यह केवल स्थानीय संघर्ष नहीं होगा बल्कि तीसरे विश्व युद्ध की संभावना को जन्म दे सकता है। अमेरिका, यूरोप और नाटो यदि ताइवान के समर्थन में खड़े होते हैं और रूस चीन के साथ, तो विश्व युद्ध की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

अब इस प्रसंग को भारत के संदर्भ से समझना अत्यंत आवश्यक है। भारत की भौगोलिक स्थिति, आर्थिक नीति, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में उसकी सामरिक भूमिका और चीन के साथ उसके सीमा विवाद ने इस पूरे परिदृश्य को हमारे लिए अत्यंत संवेदनशील बना दिया है। भारत-चीन सीमा पर 2020 के गलवान संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच विश्वास पूरी तरह टूट चुका है। चीन पाकिस्तान के माध्यम से भारत को घेरने की नीति (ष्छभ्रष्ट, ग्वादर पोर्ट) पहले ही चला रहा है, और अब यदि ताइवान-संघर्ष बढ़ता है, तो चीन दक्षिण एशिया में सैन्य और रणनीतिक दबाव बढ़ा सकता है। ऐसे में भारत का अत्यंत सावधानी से कदम चुनना अनिवार्य है।

भारत ऋक्ष का सदस्य है-जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन का संतुलन बनाने के लिए जुड़े हैं।



यदि ताइवान में संघर्ष बढ़ता है, तो अमेरिका भारत से खुलकर समर्थन की अपेक्षा करेगा। पर भारत के लिए यह निर्णय आसान नहीं, क्योंकि चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है, और सीमा से सटे देशों में अस्थिरता भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाएगी। यदि ताइवान युद्ध होता है, तो वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाय चेन टूट जाएगी, जिसका सबसे बड़ा प्रभाव भारत की तकनीकी-आर्थिक व्यवस्था पर पड़ेगा। ताइवान विश्व का 65डू70व चिप निर्माण निर्यात्रित करता है। चिप-कंपनियों के ध्वस्त होने का मतलब-मोबाइल, कंप्यूटर, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो-उद्योग, उपग्रह-तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वास्थ्य उपकरणों का ठहर जाना। दुनिया की अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ जाएगी।

भारत अभी सेमीकंडक्टर उत्पादन के राष्ट्रीय मिशन पर काम कर रहा है, पर युद्ध की स्थिति में यह प्रयास पर्याप्त सिद्ध नहीं होगा। ऊर्जा, ईंधन और आयात-निर्यात असंतुलन भी भारत को आर्थिक रूप से चुनौती देगा। रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण भारत को कच्चा तेल, गैस और खाद्य-सामग्री के मूल्य वृद्धि का जोखिम झेलना पड़ा है-ताइवान युद्ध उसका कई गुना व्यापक प्रभाव ला सकता है।

भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि क्या वह पश्चिमी दबाव में अमेरिका के पक्ष में खड़ा हो या अपनी कूटनीतिक स्वतंत्रता



ललित गर्ग

लेखक, पत्रकार, स्तंभकार

एक बार फिर एक भीषण आग ने 25 मासूम जिंदगियों को छीन लिया। गोवा के नाइट क्लब में हुई यह त्रासदी केवल आगजनी नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम की जड़ता, गैर-जिम्मेदारी और नैतिक पतन की ज्वलंत मिसाल है। गोवा का जो नाइट क्लब आग की चपेट में आया, वह नियमों की अनदेखी करके तो चलाया ही जा रहा था, उसमें आग से बचाव के उपाय भी नहीं किए गए थे। रही-सही कसर इससे पूरी हो गई कि नाइट क्लब में आने और जाने का रास्ता बेहद संकरा था। आग की चपेट में आने वालों की संख्या इसलिए अधिक बढ़ गई, क्योंकि बचने के लिए उन्होंने जिस रास्ते को सुरक्षित समझा, वहां पहले से ही लोग फंसे हुए थे। इस तरह से आनंद और उत्सव का स्थल अचानक जीवन समाधि में बदल गया, वह अनेक सवाल हमारे सामने खड़े करता है, क्या हम सीखने की क्षमता खो चुके हैं? क्यों हर हादसे के बाद जांच समितियां बनती हैं, मुआवजा घोषित होता है, कुछ दिन हंगामा होता है और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है? पूर्व में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, सूरत और अनेक शहरों में समान दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। होटल, मॉल, थिएटर, अस्पताल, फैक्ट्री, कोचिंग सेंटर-लापरवाही की आग में झूलसनों वालों की संख्या बढ़ी है, लेकिन हमारी संवेदनशीलता का स्तर छोटा होता जा रहा है। आगजनी की घटनाओं का सिलसिला तो लगातार है, परंतु सुरक्षा मानकों के प्रति हमारी उदासीनता और घोर लापरवाही भी उसनी ही स्थायी है। यह बात स्पष्ट है कि हादसे किसी तकनीकी गलती का परिणाम भर नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और राजनीतिक मिलीभगत की देन भी हैं।

गोवा अपनी पहचान पर्यटन से बनाता है। नाइट लाइफ़ समुद्री तटों का आनंद, मनोरंजन गतिविधियां और विदेशी पर्यटक इसका स्वाभाविक आकर्षण हैं। ऐसे प्रदेश में इस प्रकार का हादसा केवल मानवीय त्रासदी नहीं, बल्कि छवि और अर्थव्यवस्था का गहरा नुकसान भी है। भारत की टूरिज्म इंडस्ट्री पहले ही प्रतिस्पर्धा और सुरक्षा को लेकर चुनौतियों से जूझ रही है। यह घटना विश्व के सामने एक सवाल बनकर खड़ी है-क्या भारत सुरक्षित पर्यटन देश है? क्या यहां गैर-जिम्मेदाराना ढांचे और भ्रष्ट तंत्र के बीच किसी का जीवन सुरक्षित रखा जा सकता है? इस प्रकार के हादसों में दो बड़े चरित्र सामने आते हैं-सरकार की सुस्ती और आयोजकों की लालचपूर्ण मानसिकता। अधिकांश नाइट क्लब, बार, पार्क या मनोरंजन स्थल ऐसे होते हैं जहां प्रवेश शुल्क, अवैध संचालन और आर्थिक लाभ का बड़ा खेल चलता है। इमारतों की मंजूरी, फ़ायर सुरक्षा की अनुमति, बिजली के तारों का खरखवाव, निकास मार्ग-ये सभी चीजें फ़हलों में तो दर्ज होती हैं, लेकिन जमीन पर गायब रहती हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की सजगता की जगह 'संबंध' और 'सुविधा शुल्क' काम करता है। निरीक्षण के नाम पर औपचारिकता ढहती है और बोते हुए हादसे केवल याद बनकर रह जाते हैं।

नाइट क्लब तक पहुंचने का रास्ता इतना संकरा है कि फ़ायर ब्रिगेड की गाड़ियों को 400 मीटर दूर खड़ा होना पड़ा। सजावट के लिए ताड़ के सूखे पत्तों का इस्तेमाल



किया गया था, जिसने आग और भड़का दी। भीड़भाड़ वाली जगहों पर एंट्री से ज्यादा महत्वपूर्ण इमरजेंसी एग्जिट पॉइंट्स होते हैं, लेकिन इस क्लब में लगता है कि इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे कई लोग भटक कर किचन में पहुंच गए, जहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। यह नाइटक्लब बिना मंजूरी के चल रहा था। लोकल अथॉरिटी के मुताबिक, निर्माण अवैध था।

सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर हम हादसों को नियंति क्यों मान लेते हैं? हर घटना के बाद नेताओं के बयान आते हैं-+दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा+, +उच्च स्तरीय जांच की जाएगी+, +मुआवजा दिया जाएगा+, लेकिन क्या कभी हमने दोषियों को सजा होते देखा है? कभी किसी अधिकारी को बर्खास्त होते देखा है? क्या किसी क्लब या होटल की अनुमति स्थायी रूप से रद्द की गई? जवाब अधिकतर 'नहीं' है। यही वह सत्य है जो बताता है कि हमारा समाज हादसे को दुख तो मानता है पर समस्या नहीं मानता। अजीब विडंबना यह है कि हादसे के शिकार गरीब या आम नागरिक होते हैं, लेकिन इस त्रासदी से गुजरी व्यवस्थाओं को कोई चोट नहीं लगती। वे फिर उठते हैं, नए सजावटी बोर्ड लगा लेते हैं और जनता को फिर से आकर्षित कर लेते हैं। निवस्था में भ्रष्टाचार और मानव-मृत्यों का ह्रास दोनों मिलकर ऐसी घटनाओं को जन्म देते हैं। यह केवल प्रशासनिक नाकामी नहीं, बल्कि सामूहिक नैतिक ह्रास भी है। आयोजक केवल लाभ देखते हैं, प्रशासन केवल कागजों पर निशान देखता है; समाज घटना को क्षणिक दुख समझकर भूल जाता है।

वैश्विक स्तर पर देखें तो किसी भी विकसित या उतरदायी समाज में जन-स्थलों पर सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। नियमित निरीक्षण, कठोर दंड, मानकों का अनिवार्य पालन और पारदर्शिता बुनियादी तत्व हैं। भारत में ये मानक केवल कानूनी पुस्तकों में रहते हैं। सवाल यह नहीं कि हादसे क्यों होते हैं, सवाल यह है कि सीख क्यों नहीं ली जाती। गोवा का यह हादसा एक चेतावनी है, अकेले गोवा के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए। हम विकास, पर्यटन और आधुनिक जीवनशैली की बात करते हैं, लेकिन सुरक्षा, नियंत्रण और मानवीय संवेदनशीलता को हाशिए पर छोड़ देते हैं। यह घटना बताती है कि यदि व्यवस्था की लापरवाही और लालच के बीच नागरिक की सुरक्षा कुचलती रही तो हम आधुनिक ढांचे बनाकर भी असुरक्षित रहेंगे। किसी भी राष्ट्र की उन्नति उसके नागरिकों की सुरक्षा पर टिकी होती है, न कि केवल चमक-दमक पर।

गोवा घटना ने सरकार की छवि को ध्वस्त किया है। पर्यटन उद्योग की नींव हिलाई है और नागरिक विश्वास को चोट पहुंचाई है। गोवा के जीडीपी में पर्यटन का हिस्सा 16 प्रतिशत से ज्यादा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल की तुलना में इस साल जनवरी से सितंबर के बीच 6.23 प्रतिशत ज्यादा टूरिस्ट गोवा पहुंचे। ऐसे में यह घटना राज्य की अच्छी छवि पेश नहीं करती, जहां पहले ही टैक्सी चालकों की मनमानी और पर्यटकों के साथ अभद्रता की कुछ समस्या रही है।यदि घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकनी है तो कुछ कठोर कदम उठाने होंगे, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई, वास्तविक निरीक्षण प्रणाली, भ्रष्टाचार पर अंकुश और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर दंड। परंतु दुख यह है कि हमारा इतिहास बताता है, हम कठोर कदम उठाने से बचते हैं। आज इस त्रासदी के बाद शोक जताना पर्याप्त नहीं है। इस पर गंभीर चिंतन जरूरी है। हम केवल जिम्मेदारी टाल देने की प्रवृत्ति में नहीं जा सकते। हर हादसा हमें यही याद दिलाता है कि सुरक्षा संस्कृति, जिम्मेदार शासन और नैतिक व्यवसायिक आचरण के बिना कोई भी समाज सुरक्षित नहीं हो सकता। यह घटना केवल 25 लोगों की मौत नहीं, बल्कि चेतावनी है कि यदि हमने नहीं सीखा, तो अगली त्रासदी निकट ही खड़ी है।

हमारे नीति-नियंताओं को यह समझना होगा कि इस तरह की घटनाएं केवल जान-माल को ही क्षति नहीं पहुंचातीं, बल्कि देश की बदनामी भी कराती हैं। इस तरह की घटनाएं यही रेखांकित करती हैं कि नया और विकसित बनने के आकांक्षी भारत में नियम-कानूनों की हर स्तर पर उपेक्षा होती है और इस देश में जिम्मेदारी के साथ कोई काम मुश्किल से ही किया जाता है। मानकों और सुरक्षा उपायों की रेगुलर चेकिंग अथॉरिटीज की जिम्मेदारी है। बिना लाइसेंस चल रहे क्लब, होटल या रेस्तरां को बंद कराने के साथ यह जानना भी जरूरी है कि आखिर ये खुल कैसे जाते हैं और फिर कैसे धड़ले से चलते रहते हैं। हमें यह मानना होगा कि जीवन की कीमत केवल शब्दों में नहीं, व्यवस्था में भी झलकनी चाहिए। जब तक हमारी नीतियों में कठोरता नहीं आएगी, जब तक भ्रष्टाचार की जड़ें नहीं काटी जाएंगी और जब तक नागरिक-केंद्रित शासन स्थापित नहीं होगा, तब तक मनोरंजन के नाम पर मौतें होती रहेंगी। गोवा का नाइट क्लब हादसा केवल आग नहीं-हमारे विवेक, शासन और मानवता की विफलता है। अब यह हमारे हाथ में है कि हम इसे भूलें या इसे परिवर्तन की शुरुआत बनाएं।

यह निजी विचार है।

‘सी’ ग्रेड दूसरी सबसे खराब रेटिंग

हरिशंकर व्यास

यह भी दुनिया देख रही है। अब तक दुनिया की संस्थाएं भारत के आंकड़ों पर संदेह जताती थीं। विकास के आंकड़ों से लेकर गरीबी, प्रदूषण, शौचालय आदि के तमाम आंकड़े संदेह के घेरे में थे। कहा जा रहा था कि भारत आंकड़ों में गड़बड़ी करता है। लेकिन अब तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने भारत के आंकड़ों को 'सी' ग्रेड ही दे दिया है। यह दूसरी सबसे खराब रेटिंग होती है। आईएमएफ ने नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स को 'सी' ग्रेड दिया है, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी और ग्रांस् वैल्यू एडेड यानी जीवीए शामिल है।

सोचें, ये दोनों सबसे अहम आंकड़े होते हैं। इनको लेकर आईएमएफ ने कहा है कि 'सी' ग्रेड का मतलब है कि इन आंकड़ों में कुछ 'शॉर्टकमिंग' यानी कमी है, जिससे निगरानी की व्यवस्था प्रभावित होती है। आईएमएफ ने यह रेटिंग गुरुवार को जारी की और उसके एक दिन बाद ही भारत सरकार ने दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर के आंकड़े जारी किए।

बहरहाल, भारत के सालाना इकोनॉमिक फ़ेमवर्क को लेकर आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें नेशनल अकाउंट्स डाटा को 'सी' ग्रेड दिया गया है। वैसे ओवरऑल डाटा कैटेगरी को 'ब' ग्रेड मिला है। यानी भारत के आंकड़ों की गुणवत्ता और उनकी विश्वसनीयता या तो दोयम दर्जे की है या तीसरे दर्जे की है। आईएमएफ ने भारत की आर्थिक गणना का वेस इयर 2011-12 होने पर भी सवाल उठाया है और इसे आउटडेटेड कहा है। इसके अलावा कई और कमियां रिपोर्ट में बताई गई हैं। जाहिर है पूरी दुनिया में इस रिपोर्ट को देखा होगा। पहले से भारत के आंकड़े पर जो संदेह किया जाता है उसकी पुष्टि इससे होती है। इससे भारत का वैश्विक व्यापारिक संबंध प्रभावित होगा और विकास को लेकर किए जा रहे दावे भी प्रभावित होंगे।

ध्यान रहे भारत इस समय दुनिया के कई देशों के साथ व्यापार संधि करने के दौर में है। कई देशों के साथ व्यापार वार्ता चल रही है। अमेरिका के साथ व्यापार संधि की वार्ता चल रही है लेकिन बार बार इस पर ग्रहण लग रहा है। संभवतः इसी वजह से आईएमएफ ने यह भी कहा है कि अमेरिका की ओर से भारत के ऊपर लगाया गया 50 फीसदी टैरिफ स्थायी रूप से रहेगा। हालांकि भारत ने इसका विरोध किया है। लेकिन मुंहजबानी विरोध का कोई अर्थ नहीं है। अमेरिका के साथ तो व्यापार संधि नहीं हो हो रही है यूरोपीय संघ के साथ भी व्यापार संधि की वार्ता किसी मॉजल तक नहीं पहुंच रही है।

हालांकि भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी ईएफटीए के साथ एक संधि की है। परंतु वह व्यापार व आर्थिक साझीदारी का समझौता यानी टीडीपीए है। यूरोपीय संघ के साथ भारत की मुक्त व्यापार संधि यानी एफटीए की वार्ता काफी समय से चल रही है। सोचें, जब से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर शुरू किया है तब से दुनिया के अनेक देशों ने व्यापार संधि कर ली है। चीन की भी व्यापार संधि अमेरिका के साथ हो गई है। लेकिन भारत की संधि न तो अमेरिका से हो रही है और यूरोपीय संघ के साथ हो रही है। यह निजी विचार है।

संजीव ठाकुर चिंतक, लेखक,

काशी तमिल संगमम् के अंतर्गत पुलिसकर्मी और नमो घाट पर रहने वाले परिवार सीख रहे हैं तमिल

काशी तमिल संगमम् 4.0 का इस वर्ष का मुख्य विषय «तमिल सीखें - तमिल करकलाम» है, जिसका उद्देश्य उत्तर और दक्षिण भारत के बीच भाषाई और सांस्कृतिक सेतु को और अधिक सशक्त बनाना है। इसी थीम के अंतर्गत वाराणसी में एक प्रेरणादायक और मन को छू लेने वाली पहल देखने को मिली। एक ओर, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों ने तमिल भाषा का प्रशिक्षण लिया ताकि काशी आने वाले तमिलभाषी श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सहायता वे और भी सहज तथा प्रभावी ढंग से कर सकें। उन्हें दैनिक संवाद, अभिवादन तथा यात्रियों से सामान्य बातचीत के लिए आवश्यक तमिल वाक्य सिखाए गए।

भारत पारंपरिक चिकित्सा के माध्यम से संतुलन बहाल करने में दुनिया में अग्रणी है: श्री प्रताप राव

शिखर सम्मेलन पारंपरिक चिकित्सा के साक्ष्य-आधारित एकीकरण को प्रोत्साहन देगा: डॉ. पूनम खेत्रपाल

वैश्विक शिखर सम्मेलन आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 17-19 दिसंबर 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा

शिखर सम्मेलन वैज्ञानिक सत्यापन, डिजिटल स्वास्थ्य, जैव विविधता संरक्षण और पारंपरिक चिकित्सा में वैश्विक सहयोग पर केंद्रित होगा

पीआईबी

आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में द्वितीय विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन से पहले एक पूर्वावलोकन पर एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। यह शिखर सम्मेलन 17-19 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा।

केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री प्रतापराव जाधव ने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि भारत 2023 में गुजरात में आयोजित पहले सफल आयोजन के बाद, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। उन्होंने कहा कि यह शिखर सम्मेलन मानवता के स्वास्थ्य, खुशी और कल्याण के लिए पारंपरिक चिकित्सा को मुख्यधारा में लाने के सामूहिक वैश्विक प्रयास में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो भारत के «सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामयाः» के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

श्री जाधव ने बताया कि इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय «संतुलन बहाल करना: स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास» है। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के मंत्री, नीति निर्माता, वैश्विक स्वास्थ्य नेता, शोधकर्ता, विशेषज्ञ, उद्योग प्रतिनिधि और



चिकित्सक एक साथ आएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि इसमें 100 से अधिक देशों की भागीदारी अपेक्षित है।

केंद्रीय मंत्री महोदय ने घोषणा की कि आयुष मंत्रालय भारत के सबसे प्रसिद्ध और वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किए गए औषधीय पौधों में से एक, अश्वगंधा पर एक समर्पित कार्यक्रम आयोजित करेगा, जिसमें पारंपरिक और समकालीन स्वास्थ्य पद्धतियों में इसके महत्व पर प्रकाश डाला जाएगा।

केंद्रीय मंत्री महोदय ने पारंपरिक चिकित्सा में भारत के वैश्विक नेतृत्व पर जोर देते हुए कहा कि आयुष प्रणालियाँ - आयुर्वेद, योग और

प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा-रिग्पा और होम्योपैथी - सदियों से लोगों की सेवा करती रही हैं और आज समग्र स्वास्थ्य के लिए विश्वसनीय समाधान के रूप में दुनिया भर में मान्यता प्राप्त हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ साझेदारी में गुजरात के जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र की स्थापना, भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों में बढ़ते वैश्विक विश्वास को दर्शाती है।

श्री जाधव ने आगामी शिखर सम्मेलन की योजना बनाने में आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन के निरंतर प्रयासों की प्रशंसा की और पारंपरिक चिकित्सा में जागरूकता बढ़ाने और जनता के विश्वास

को मजबूत करने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया।

केंद्रीय मंत्री महोदय ने बताया कि शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के शामिल होने की संभावना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि शिखर सम्मेलन से प्राप्त विचार-विमर्श और सहयोग विश्व को स्वास्थ्य सेवा के अधिक समग्र, समावेशी और टिकाऊ भविष्य की ओर ले जाएंगे।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक एमेरिटस और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक की पारंपरिक चिकित्सा पर वरिष्ठ सलाहकार डॉ. पूनम खेत्रपाल ने इस बात पर जोर दिया कि पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग को आगे बढ़ाने में एक प्रमुख उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि 100 से अधिक देशों की भागीदारी के साथ, यह शिखर सम्मेलन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों में पारंपरिक, पूरक, एकीकृत और स्वदेशी औषधियों के साक्ष्य-आधारित, न्यायसंगत और सतत एकीकरण के लिए एक दशक लंबी रूपरेखा को आकार देगा।

पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक निर्भरता पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने अनुसंधान, नवाचार और नियामक सुदृढ़ीकरण के माध्यम से साक्ष्य अंतराल को पाटने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया।

शिखर सम्मेलन के विचार-विमर्श के एक भाग के रूप में, «अश्वगंधा: पारंपरिक ज्ञान से वैश्विक प्रभाव तक - अग्रणी वैश्विक विशेषज्ञों के दृष्टिकोण» शीर्षक से एक केंद्रित कार्यक्रम 17-19 दिसंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा। डब्ल्यूएचओ-जीटीएमसी द्वारा आयुष मंत्रालय के सहयोग से आयोजित यह सत्र अश्वगंधा की वैज्ञानिक समझ को मजबूत करने के लिए प्रमुख शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और चिकित्सकों को एक साथ लाएगा। चर्चाओं में इसके एडाप्टोजेनिक, न्यूरोप्रोटेक्टिव और इम्यूनोमॉडुलेटरी गुणों पर समकालीन साक्ष्यों पर प्रकाश डाला जाएगा, साथ ही पारंपरिक ज्ञान से प्राप्त विचारों पर भी प्रकाश डाला जाएगा। सुरक्षा आकलन पर जोर देते हुए, इस सत्र का उद्देश्य उच्च-गुणवत्ता वाले, साक्ष्य-आधारित अश्वगंधा उत्पादों की वैश्विक स्वीकृति को और बढ़ावा देना है।

अभाविप इकाई, गोबरा नवापारा ने डॉ. भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस को सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाया

नवापारा राजिम।

अभाविप इकाई, गोबरा नवापारा ने डॉ. बी.आर. अंबेडकर जी की परिनिर्वाण दिवस को सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर नगर के चंपारण चौक में स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित किया गया।

अंबेडकर एक प्रखर राष्ट्रवादी व मानवता के पुजारी थे। अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने «भारत माता की जय», «छत्तीसगढ़ महतारी की जय», «वन्दे मातरम्» व «डॉ. भीमराव

अंबेडकर अमर रहें» के नारे लगाए। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व नगर मंत्री दीपक साहू, नगर सह मंत्री दिपेश सेन, कोषाध्यक्ष अभिषेक कंसारी, नगर एस.एफ.एस. प्रमुख आयुष रजक, खेलों भारत प्रमुख धर्मेन्द्र साहू, नगर कार्यकारिणी सदस्य सोम निर्मलकर, प्रेम साहू, जगमोहन साहू, श्लोक शर्मा सहित अभाविप के समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कोयला आधारित थर्मल पावर उत्पादन के कार्बन उत्सर्जन और पर्यावरणगत प्रभाव का समाधान

कोयला आधारित थर्मल पावर उत्पादन के कार्बन उत्सर्जन और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए सरकार निम्नलिखित कदम उठा रही है: (i) विद्युत मंत्रालय कुशल सुपरक्रिटिकल/अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा दे रहा है जो अधिक कुशल हैं और प्रति यूनिट विद्युत उत्पादन में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करती हैं। 31.10.2025 तक क्रमशः 70,190 मेगावाट (101 इकाइयाँ) और 7,680 मेगावाट (11 इकाइयाँ) की कुल क्षमता वाली सुपरक्रिटिकल/अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल इकाइयाँ चालू हो चुकी हैं। (ii) ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए, विभिन्न थर्मल पावर संयंत्रों में परफॉर्म, अवीव और ट्रेड (पीएटी) स्कौम लागू की गई हैं। ऊर्जा दक्षता में सुधार से थर्मल पावर उत्पादन में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आती है।

विजय मिश्रा ‘अमित’ को सामाजिक समरसता सम्मान समाजहित में आगे आएँ गुणीजन – डॉ सुखदेव सरस

रायपुर। बहुप्रतिष्ठित समाज गौरव विकास समिति द्वारा प्रदेश के वरिष्ठ रंगकर्मी- कलमकार विजय मिश्रा ‘अमित’ को ‘सामाजिक समरसता सम्मान’ से विभूषित किया गया। सिविल लाइन रायपुर स्थित कुंदावन सभागार में आयोजित सामाजिक प्रतिभा सम्मान समारोह 2025 के मुख्य अतिथि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. गिरिश चट्टेल ने उन्हें साल श्रीफल, सम्मान पत्र देकर अलंकृत किया। कुलपति श्री चट्टेल ने छत्तीसगढ़ की मिट्टी में निहित रीति- रिवाज संस्कार-संस्कृति को बनाए रखने का आह्वान किया।इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि पूर्व अपर कलेक्टर नोहर राम साहू

गुरु गोरखनाथ अलंकृत आचार्य पुनाराम साहू राज तथा समारोह के संयोजक डॉक्टर सुखदेव राम साहू ‘सरस’ ने छत्तीसगढ़ को प्रतिभाओं का गढ़ कहते हुए इसके भविष्य को उज्जवल बताया। कार्यक्रम का संजालन ठेठ छत्तीसगढ़ी में करते हुए ऋतुराज साहू ने विभूषित विजय मिश्रा की कला साहित्य यात्रा पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया हिंदी लोक- रंगमंचों पर वे पिछले पांच दशक से सतत सक्रिय हैं। हिमाचल प्रदेश की राष्ट्रीय सांस्कृतिक मंच में बलराज साहनी अवार्ड से विजय मिश्रा अलंकृत हैं। कार्यक्रम के अंत में डॉ सुखदेव ने आभार प्रदर्शन किया।

निर्यात प्रोत्साहन एमएसएमई निर्यातकों के लिए व्यापार वित्त सुविधा पर केंद्रित है, निर्यात दिशा गैर-वित्तीय सहायता प्रदान करती है

एमएसएमई की क्षमता निर्माण और घरेलू तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना और एमएसएमई प्रतिस्पर्धी (लीन) योजना

पीआईबी -

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्रों से निर्यात के हालिया रुझानों के अनुसार कुल व्यापारिक निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान 2023-24 में 45.74 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में 48.55 प्रतिशत हो गया है। सरकार ने एमएसएमई सहित अन्य क्षेत्रों से समग्र निर्यात को मजबूत करने के लिए निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत, निर्यात प्रोत्साहन के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी, जो एमएसएमई निर्यातकों के लिए व्यापार वित्त सुविधा पर केंद्रित है। इसी तरह से निर्यात दिशा, निर्यात-गुणवत्ता और अनुपालन

सहायता, बाजार-पहुंच हस्तक्षेप, लॉजिस्टिक सुविधा और निर्यात व्यवस्था निर्माण के उपायों सहित गैर-वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा, हाल ही में किए गए व्यापक जीएसटी सुधारों से, एमएसएमई को मजबूती मिलेगी। कम जीएसटी दरों ने कच्चे माल और सेवाओं को अधिक किफायती बना दिया है जिससे छोटे और मध्यम उद्यमों और स्टार्ट-अप्स को परिचालन बढ़ाने, नवाचार में निवेश करने और घरेलू और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रेरित किया गया है।

सरकार ने वैश्विक मूल्य शृंखला में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान से मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स के लिए व्यापक और एकीकृत योजना संभव हुआ है।

PTRS में टंड में सुबह 8 बजे परीक्षा को लेकर हंगामा ; NSUI ने कुलपति को सौंपा ज्ञापन

लोकशक्ति

पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में NSUI प्रदेश उपाध्यक्ष (SM) पुनेश्वर लहरे के नेतृत्व में छात्र प्रतिनिधिमंडल ने कुलपति महोदय को ज्ञापन सौंपते हुए दिसंबर जनवरी सत्र की सेमेस्टर परीक्षाओं के समय में परिवर्तन तथा प्रश्नपत्र वितरण में होने वाली अव्यवस्थाओं पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। पुनेश्वर लहरे ने बताया कि कड़कड़ती टंड में सुबह 8 बजे परीक्षा आयोजित करना विद्यार्थियों के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। दूर-दूर से आने वाले छात्र-छात्राओं को परीक्षा दूर तक पहुँचने में भारी कठिनाई होती है, वहीं टंड के कारण उत्तर-झुलखन क्षमता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति न केवल विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि उनके परीक्षा-प्रदर्शन को भी प्रभावित कर रही है।

पुनेश्वर लहरे यह भी बताया कि विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में हर वर्ष प्रश्नपत्र वितरण को लेकर गंभीर त्रुटियाँ देखने को मिलती हैं। कई केंद्रों में प्रश्नपत्र निर्धारित समय से देर से पहुँचते हैं, जबकि अनेक बार गलत विषय के प्रश्नपत्र भी बांट दिए जाते हैं। ऐसी



लापरवाहियों के कारण विद्यार्थियों का कीमती समय नष्ट होता है और मानसिक दबाव बढ़ जाता है। NSUI ने ज्ञापन में दो प्रमुख मांगें रखीं- परीक्षा का समय बदलकर सुबह 9 या 10 बजे के बाद निर्धारित किया जाए। प्रश्नपत्र

वितरण प्रक्रिया को पूर्णतः त्रुटिरहित बनाने के लिए सख्त निगरानी, जवाबदेही एवं दंडात्मक व्यवस्था लागू की जाए। NSUI ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि इन समस्याओं का समाधान शीघ्र नहीं किया गया, तो संगठन

विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ छात्रहित में धेराव करने के लिए बाध्य होगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान पुनेश्वर लहरे, अंकित बंजारे, साहिल मिरी, मोनेंद्र मानिकपुरी, विनय भोई, राजेंद्र सिदार सहित कई छात्र उपस्थित रहे।

जिले में 8 से 31 दिसम्बर 2025 तक चलेगा सघन कुष्ठ खोज अभियान

जांजगीर-चांपा / कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे के निर्देशन में जिले में 08 से 31 दिसम्बर 2025 तक सघन कुष्ठ खोज अभियान चलाया जाएगा। अभियान का उद्देश्य जिले के सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कुष्ठ रोग के उन्मूलन के उद्देश्य से समुदाय में कुष्ठ रोग के संक्रमण को रोकने हेतु प्रत्येक रोगियों का प्रारंभिक अवस्था में पहचान कर उपचार से लाभान्वित करना है। इस संबंध में कलेक्टर श्री महोबे ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में बैठक लेकर स्वास्थ्य विभाग एवं सर्वे टीम घर-घर जाकर सदस्यों की जांच एवं जनजागरूकता प्राथमिकता के साथ करने के निर्देश दिये। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री गोकुल रावटे, अपर कलेक्टर श्री आर के तंबोली सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. उमेश कुमार मरकाम ने बताया कि सर्वेक्षण कार्य - प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 घरों में तथा शहरी क्षेत्रों में 20 से 25 घरों में, संधारण प्रपत्र-1, घर की बाहरी दीवार पर गेरु से टिक का निशान लगाया जाएगा एवं एल/दिनांक लिखा जाएगा। संकास्पद कुष्ठ मरीजों का सत्यापन-कुष्ठ संदेहास्पद मरीज हेतु ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष/एन.एम.ए. द्वारा जांच कर कुष्ठ की पुष्टि कर पुनः मेडिकल ऑफिसर से पुष्टि कराया जाना है। पीबी/एमबी पुष्टि कर एमडीटी की दवा से पूर्ण उपचार सुनिश्चित होगा। धनात्मक कुष्ठ रोगियों की निकुस्ट 2.0 पोर्टल में एंट्री। नये कुष्ठ मरीजों का पुष्टि - पास के सी.एच.सी./पी.एच.सी. में चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जावेगा। मॉनिटरिंग टीम एन.एम.ए., स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, आर.एच.ओ., एम.टी. - 10 प्रतिशत घरों का औचक निरीक्षण प्रतिदिन किया जावेगा प्रतिवेदन फर्म (प्रपत्र-3) खण्ड चिकित्सा अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। रिपोर्टिंग डाटा प्रबंधक, आर.एच.ओ., एम.टी., पी.ए.डी.ए. -अपने कार्यक्षेत्र की



सभी मितानिन से चिह्नंकित संभावित रोगियों की सूची सलग्न प्रपत्र-2 में दर्ज कर संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में जमा करें। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - सूची की कम्प्यूटर प्रविष्टि प्रारूप अनुसार की जावेगी। जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री उत्कर्ष तिवारी ने राज्य स्तर पर 03 दिसम्बर 2025 को जिला कुष्ठ अधिकारी व टीम, 04 दिसम्बर 2025 को बी.एम.ओ., बी.पी.एम., बी.ई.टी.ओ. एन.एम.ए. को 05 दिसम्बर 2025 को जिले के सभी ब्लॉक में स्वास्थ्य अमला एवं मितानिन बी.सी., एम.टी., 06 दिसम्बर 2025 को सभी उप स्वास्थ्य केन्द्र सर्वे टीम महिला 1 एवं पुरुष 1 को

प्रशिक्षण दिया गया। ब्लॉक - अकलतरा 212, बलौदा 195, बम्हनीडीह 254, नवागढ़ 295, पामगढ़ 201 एवं जांजगीर शहरी में 43, कुल -1200 सर्वे टीम (1 महिला एवं पुरुष) सघन कुष्ठ खोज अभियान एल.सी.डी.सी. में घर-घर जाकर कुष्ठ संभावित व्यक्तियों का सर्वेक्षण किये जाने की जानकारी दी। एन.एम.ए. श्री के.के. थवाईत ने बताया कि शासन का लक्ष्य प्रति 10 हजार की आबादी में 1 या 1 से कम नए कुष्ठ रोगी पाये जाने का लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ राज्य में जांजगीर-चाम्पा जिला भी हाई एण्डेमीक जिला में आता है। जिसके लिए सघन कुष्ठ खोज अभियान चलाया जा रहा है।

मितानिन दिवस पर ग्राम पंचायत गर्रापार के जनप्रतिनिधि एवं ग्रामवासियों द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान



राजनंदगांव /छुरिया, गर्रापार। मितानिन दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत गर्रापार में स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली मितानिन दीदी, एएनएम एवं सीएचओ मैडम का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। ग्राम पंचायत की ओर से सभी स्वास्थ्य कर्मियों को साड़ी एवं श्रोप्ल भेंट कर सम्मानित किया गया। ग्रामवासियों ने स्वास्थ्य सेवाओं में उनके अमूल्य योगदान का प्रशंसा करते हुए इनके द्वारा किए जा रहे सेवा के लिए उत्साहित किया गया । कार्यक्रम में मुख्य रूप से सरपंच अजय साहू, उपसरपंच नीलम कोराम पंच कविता सिन्हा, रैन बाई मंडावी, परमीन मरकाम,सीमा मंडावी,शत्रु राम गावड़े,कोमल दास साहू गांव की

महिलाएँ, दीदीगण तथा बच्चे बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि मितानिन, एएनएम और सीएचओ ग्रामीण स्वास्थ्य तंत्र की मजबूत कड़ी हैं, जो घर-घर तक स्वास्थ्य जागरूकता व सेवाएँ पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनकी निःस्वार्थ सेवा भावना के कारण ही गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं का सुचारु संचालन संभव हो सका है। ग्राम पंचायत गर्रापार की ओर से सभी स्वास्थ्य कर्मियों का आभार व्यक्त करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई और उनके प्रत्येक कार्य में सहयोग प्रदान करने का विश्वास दिलाते हुए समापन की घोषणा की गई ।

पीएम जनमन योजना ने बदली जिंदगी की तस्वीर : सुदूर ग्राम कुर्रा के रतिराम को मिला सपनों का पक्का आशियाना

सम्मान और सुरक्षित जीवन की ओर बढ़ते कदम

रायपुर, लोकशक्ति

किसी भी सरकारी योजना का वास्तविक महत्व तभी सिद्ध होता है, जब उसका लाभ जमीनी स्तर पर आम नागरिक के जीवन में सकारात्मक और स्थायी परिवर्तन लाए। ऐसी ही एक सशक्त योजना है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन), जिसका प्रभाव रायगढ़ जिले में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। इस योजना के अंतर्गत लैलूंगा विकासखंड के सुदूर ग्राम कुर्रा के निवासी श्री रतिराम बिरहोर को उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना-पक्का और सुरक्षित आवास-साकार हुआ।

जीवन में स्थायित्व, आत्मविश्वास और सम्मान भी लेकर आया पीएम-जनमन

वर्षों तक कच्चे मकान में रहकर बरसात, ठंड और जहरीले जीव-जंतुओं के खतरे के बीच जीवन-यापन करने वाले रतिराम और उनका परिवार जब पीएम जनमन योजना के तहत स्वीकृत आवास में प्रवेश किया, तो वह क्षण उनके लिए अविस्मरणीय बन गया। आवास स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और

निर्धारित समय में पूर्ण भी हुआ। नया पक्का घर न केवल उन्हें सुरक्षा प्रदान कर रहा है, बल्कि उनके जीवन में स्थायित्व, आत्मविश्वास और सम्मान भी लेकर आया है।

जनजातीय समूहों के सर्वांगीण विकास के लिए एक महत्वाकांक्षी मिशन

रतिराम का कहना है कि पहले जिस घर में रहना मजबूरी था, वहीं अब पक्के मकान में रहना गर्व की अनुभूति देता है। उल्लेखनीय है कि पीएम-जनमन योजना, जिसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023 में की गई, विशेष रूप से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के सर्वांगीण विकास के लिए एक महत्वाकांक्षी मिशन है। इस अभियान का उद्देश्य आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, बिजली, आजीविका और संपर्क जैसी बुनियादी सुविधाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना है। गौरतलब है कि पीएम जनमन योजना आज केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि आदिवासी समुदायों के लिए न्याय, समानता और आत्मसम्मान का मजबूत आधार बन चुकी है। ग्राम कुर्रा के रतिराम की कहानी इस बात का सशक्त उदाहरण है कि जब योजनाएँ सही ढंग से लागू होती हैं, तो वे लोगों की तस्वीर ही नहीं, तकदीर भी



कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने ली साप्ताहिक समय सीमा की बैठक



धान खरीदी पर चौकस निगरानी नोडल अधिकारियों को सख्त निर्देश, कोचियों-बिचौलियों पर सख्त करे कार्यवाही

जिले में चल रहे सड़क मरम्मत के कार्यों में गुणवत्ता सर्वोपरि, कलेक्टर ने निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने और प्रारंभ-अप्रारंभ कार्यों की सूची उपलब्ध कराने के लिए निर्देश

जांजगीर-चांपा / संवाददाता

कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समीक्षा की। उन्होंने नोडल अधिकारियों एवं संबंधित अधिकारियों को धान खरीदी केंद्रों की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। किसानों की सुविधा, पारदर्शिता और व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कोचियों-बिचौलियों पर कड़ी निगरानी रखने और अनियमितता पर तत्काल कार्यवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अन्य जिलों से धान की अवैध खरीदी, भंडारण व परिवहन पर सख्त रोक लगाएँ तथा कार्यवाई करें।



कलेक्टर ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि 11 दिसम्बर 2025 तक समस्त गणना पत्रकों के डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण किया जाना है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि टीम वर्क के साथ मिशन मोड में सभी कार्य समय-सीमा में पूर्ण करें। उन्होंने रोजगार एवं आजीविका लोन मेला को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कहा कि इसके साथ ही प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को तेजी से क्रियान्वित करने और शिविरों के माध्यम से व्यापक जनजागरूकता करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि विभिन्न विभागों में बैठकों में खातों में लंबी अवधि से निष्क्रिय रूप से जमा पाए गए हैं। इन खातों को सक्रिय करने के लिए 9 से 11 दिसंबर 2025 तक कलेक्टोरेट सभाकक्ष में शिविर आयोजित किया जा रहा है।

कलेक्टर श्री महोबे ने कुष्ठ रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जिले में सघन कुष्ठ रोग उन्मूलन अभियान 8 से 31 दिसम्बर तक अभियान चलाया जाएगा।

उन्होंने स्वास्थ्य एवं संबंधित विभाग को घर-घर सर्वे, स्क्रीनिंग, उपचार, संपर्क एवं जनजागरूकता गतिविधियों को तेज गति से संचालित करने को कहा। कलेक्टर ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में टीमों के माध्यम से सक्रिय खोज अभियान चलाकर संभावित रोगियों की पहचान करने तथा समय पर उपचार उपलब्ध कराने निर्देशित किया। साथ ही आमजन को बीमारी के लक्षण, जांच एवं मुफ्त उपचार की जानकारी व्यापक स्तर पर पहुंचाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल के अनुसार सभी खरीदी प्रक्रिया अनिवार्यतः निर्धारित नियमों एवं दिशानिर्देशों के तहत की जाएगी।

कलेक्टर ने आदिवासी विकास विभाग को निर्देशित किया है कि विभाग में लंबित सभी छत्रवृत्ति प्रकरणों का शीघ्र और प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने हितग्राही मूलक योजनाओं, महतारी वंदन योजना की सभी हितग्राहियों का आधार सीडिंग कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग को अपार आईडी तैयार करने

की प्रक्रिया में तेजी लाने, विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा की तैयारियों की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु विशेष कक्षाओं, मार्गदर्शन सत्रों और अभ्यास कार्यक्रम को प्रभावी रूप से संचालित करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में रोजगार मेला एवं आजीविका मेला आयोजित कर अधिक से अधिक युवाओं और स्व-सहायता समूहों को अवसर प्रदान किए जाएं। साथ ही वय वंदना योजना के पात्र वरिष्ठ नागरिकों को समय पर लाभ दिलाने हेतु उनके आयुष्मान कार्ड शीघ्र बनवाए जाएं, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ बिना किसी बाधा के उपलब्ध हो सके। उन्होंने 11 से 12 दिसम्बर तक आयोजित होने वाले युवा महोत्सव के आयोजन की तैयारियों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री गोकुल रावटे, अपर कलेक्टर श्री आर.के. तंबोली, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती सिन्ध्या तिवारी सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

कलेक्टर ने जनदर्शन में पहुंचे जन समान्य की समस्याओं को संवेदनशीलता पूर्वक सुना



जनदर्शन में आज कुल 78 आवेदन हुए प्राप्त

जांजगीर-चांपा / कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जनदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे जनसामान्य की शिकायतों एवं मांग जैसे समस्याओं को संवेदनशीलतापूर्वक सुना और उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं को प्राथमिकता के साथ और समय-सीमा में निराकरण के निर्देश दिए। आज जनदर्शन में कुल 78 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आज जनदर्शन में ग्राम महंत निवासी श्री

भैयाराम नट भूमि रकबा को कॉम्प्यूटीकृत करने, ग्राम चंदनिया निवासी श्री टिम्पन सिंह द्वारा मुआवजा दिलाने, जनवाद पंचायत बम्हनीडीह अंतर्गत ग्राम पंचायत खपरीडीह निवासी श्रीमती प्रेम बाई धनुहार द्वारा राशनकार्ड बनवाने, ग्राम पौना के श्री भैरो प्रसाद मिश्रा द्वारा सीमांकन करवाने एवं नया पच्ची बनवाने संबंधी आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर श्री महोबे ने प्राप्त सभी आवेदनों का संबंधित अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्यवाही करते हुए निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। जनदर्शन में अन्य आवेदकों द्वारा नामांतरण, भूमि सीमांकन, आर्थिक सहायता, पीएम किसान सम्मान निधि, राशन कार्ड बनाने सहित कुल 78 आवेदन प्राप्त हुए।

खास खबर

जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा की शासी परिषद की बैठक आज

कोरबा कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा की अध्यक्षता में जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा की शासी परिषद की बैठक 06 दिसंबर को प्रातः 11 बजे कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष कोरबा में आयोजित की गई है।

अंशकालिक योग / खेल शिक्षक / प्रशिक्षक एवं अंशकालीन संगीत प्रशिक्षक पद हेतु काउंसिलिंग 08 दिसंबर को

कोरबा)। जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा के अंतर्गत कोरबा जिले में संचालित पीएमश्री विद्यालयों में अंशकालिक योग / खेल शिक्षक / प्रशिक्षक एवं अंशकालीन संगीत प्रशिक्षक पद हेतु 26 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित किया गया था। विभागीय जांच/जिला समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर पात्र / अपात्र का मेरिट सूची के क्रमानुसार काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थियों को दिनांक 08 दिसंबर 2025 को दोपहर 01 तक आमंत्रित किया गया है।

तुमान में सनसनीखेज घटना: पत्नी ने किया पति का कत्ल, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

कोरबा कटघोरा थाना क्षेत्र के तुमान गांव में 4 और 5 दिसंबर की दरमियानी रात एक दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। घरेलू विवाद के बीच पत्नी ने अपने ही पति की हत्या कर दी, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। तुमान गांव निवासी मनहरण यादव और उसकी पत्नी कविता यादव के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। जानकारी के अनुसार, मनहरण यादव शराब का ज्यादा आदी था, जिससे रोजाना पति-पत्नी के बीच तकरार होती थी। घटना वाली रात भी दोनों के बीच बहसबाजी बढ़ गई।विवाद इतना बढ़ा कि गुस्से में पत्नी कविता यादव ने पति पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कटघोरा पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का मुआयना किया। पुलिस ने मुर्क के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी पत्नी कविता यादव को हिरासत में लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वह फिलहाल पुलिस कस्टडी में है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा कोरबा में जिला स्तरीय आवास मेला का आयोजन 8 से 12 दिसंबर तक

कोरबा। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल हमेषा से ही लोगों को आवासीय कालोनी का निर्माण कर विभिन्न वर्गों के लिए किफायती दर पर भवन उपलब्ध कराता है। इसी कड़ी में राज्य बनने के 25 वर्ष पूरा होने पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा प्रदेश स्तर पर 2000 करोड़ की नई आवासीय योजनाएं भव्य सभ्मत राज्य स्तरीय आवास मेला रायपुर में 23 नवंबर 2025 को शुरू की गई है। मेले में खरमोरा कोरबा अंतर्गत 370 फ्लैट के आवासीय योजना का भी शुभारंभ किया गया है, जिसमें एम.आई.जी., एल.आई.जी. एवं ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैट बनाए जाएंगें।

बालको में जिला स्तरीय मॉक ड्रिल का सफल आयोजन

कोरबा-बालकोनगर संवाददाता । वेदांता समूह की कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) ने डिट्टी डायरेक्टर, इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी, कोरबा श्री विजय सिंह पोटाई के दिशा-निर्देश में जिला स्तरीय मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया। यह मॉक ड्रिल आपातकालीन सहयोगी संस्थान की सहभागिता से आयोजित की गई, जिसमें 7 उद्योगों के 27 प्रतिनिधियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। मॉक ड्रिल में कोरबा के विभिन्न औद्योगिक संस्थान, पावर लिमिटेड (पूर्व में लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड), एचटीपीएस कोरबा वेस्ट, माइंस रेस्क्यू स्टेशन एवं फ़यर सर्विसेस एसईसीएल कुसमुंडा एरिया, एनटीपीसी कोरबा, डीएसपीएम टीपीएस कोरबा ईस्ट, आईओसीएल कोरबा टर्मिनल एवं आईओसीएल कुसमुंडा शामिल थे। बालको के सीओओ (पावर) संतोष सिन्हा ने डिट्टी डायरेक्टर का स्वागत किया। मॉक ड्रिल से पूर्व घटना और आपातकालीन योजना पर विस्तार से चर्चा हुई। बालको के प्रमुख एचएसई एंड एस बी. शिवकुमार द्वारा प्लांट सेफ्टी, रोड सेफ्टी, फ़यर जागरूकता एवं मॉक ड्रिल क्षेत्र से संबंधित सीख प्रस्तुति दी गई। 1200 मेगावाट पॉवर प्लांट में अग्निकांड की आपात स्थिति पर मॉक ड्रिल की गई, जिसमें एक संभावित औद्योगिक दुर्घटना का अनुकरण किया गया।

डीएमएफसे एक दिन मॉडल जिला बनेगा कोरबा

शहर के सड़कों के डामरीकरण और बेलगरी बस्ती क्षेत्र में पुल-सड़क निर्माण कर यातायात को बेहतर बनाने मंत्री ने दिये निर्देश

वित्तीय वर्ष 2025-26 के स्वीकृत कार्यों की प्रगति, कार्योंतर स्वीकृति एवं नई कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा

शासी परिषद की बैठक में डीएमएफराशि व्यय के नए नियमों की दी गई जानकारी’

कोरबा । छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य, उद्योग, आबकारी, सार्वजनिक उपक्रम एवं श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन के मुख्य आतिथ्य में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला खनिज संस्थान न्यास कोरबा की शासी परिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान स्वीकृत कार्यों की प्रगति, किए गए कार्यों की कार्योंतर स्वीकृति तथा आगामी वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर विधायक कटघोरा श्री प्रेमचंद पटेल, विधायक पाली-तानाखार क्षेत्र श्री तुलेश्वर सिंह मरकाम, विधायक रामपुर के प्रतिनिधि, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. पवन कुमार सिंह, महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे, जबकि पदेन अध्यक्ष कलेक्टर श्री अजीत वसंत, वनमंडलाधिकारी कोरबा श्रीमती



प्रेमलता यादव, कटघोरा के डीएफओ श्री कुमार निशांत, आयुक्त नगर निगम श्री आशुतोष पांडेय, जिला पंचायत सीईओ श्री दिनेश नाग, सांसद-विधायक प्रतिनिधि, अपर कलेक्टर श्री देवेन्द्र पटेल, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती माधुरी सोम, एसडीएम कोरबा श्री सरोज महिलागे सहित अन्य विभागीय अधिकारी बैठक में सम्मिलित हुए। बैठक में डीएमएफअंतर्गत विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर

विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। चर्चा के दौरान मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि जिले के समग्र विकास में डीएमएफ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग एवं जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास के कार्य तेजी से संचालित किए जा रहे हैं और यदि यही गति बनी रही, तो कोरबा शीघ्र ही एक मॉडल जिले के रूप में विकसित होगा। उन्होंने कहा कि

डीएमएफके माध्यम से जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, पौष्टिक आहार, पीवीटीडी समुदाय को रोजगार, नीट की कोचिंग जैसी जनहितैषी योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे आमजन की आवश्यकताओं का समाधान भी होगा और क्षेत्र के समग्र विकास को मजबूती भी मिलेगी। उन्होंने डीएमएफके माध्यम से शहर के सड़कों में डामरीकरण करने, बेलगरी बस्ती क्षेत्र में पुल और सड़क का निर्माण कर यातायात को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। मंत्री श्री देवांगन ने यह भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए डीएमएफराशि का प्रावधान सुनिश्चित किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की भी मंशा है कि खनन प्रभावित क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार हो और जनता को बेहतर सेवाएँ उपलब्ध हों। कलेक्टर एवं जिला प्रशासन इस दिशा में कार्य कर रहा है तथा डीएमएफ का उपयोग उच्च प्राथमिकता वाले विकास कार्यों में पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता के साथ किया जा रहा है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्वीकृत कार्यों की नियमित समीक्षा सुनिश्चित की जाए, निर्माण कार्य समय-सीमा में पूर्ण हों और गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी न हो। साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष के लिए विभागीय कार्यों का प्राकलन तैयार कर समय पर शासन को प्रेषित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देशन में बुका-सतरंगा एवं झोराघाट क्षेत्र में पर्यटन विकास के लिए प्रस्तुत प्रस्तावों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इससे कोरबा जिले की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगी।

RPF पोस्ट में चली गोली, प्रधान आरक्षक की मौके पर मौत



रायगढ़ ।

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ रेलवे स्टेशन स्थित RPF पोस्ट में सुबह एक गंभीर घटना हुई। ड्यूटी के दौरान आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि एक प्रधान आरक्षक ने अपने ही साथी पर गोली चला दी। इसमें प्रधान आरक्षक

पी.के. मिश्रा की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी प्रधान आरक्षक के.एस. लादेर को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। घटना सुबह करीब चार बजे की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई जो अचानक हिंसक हो

गई। कहा जा रहा है कि इसी दौरान लादेर ने अपनी सर्विस राइफल से गोली चला दी। गोली लगते ही मिश्रा गिर पड़े और उनकी वहीं मौत हो गई।

जांच जारी

सूचना मिलते ही रायगढ़ एसपी

दिव्यांग पटेल सहित जिला और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। रेलवे स्टेशन परिसर और RPF पोस्ट को सील कर दिया गया है। आरोपी से पूछताछ चल रही है और पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है।

वेदांता एल्युमिनियम का बड़ा सामाजिक कदम, 4,000 घंटे का संकल्प, लाखों चेहरे पर मुस्कान

कोरबा-बालकोनगर संवाददाता ।

अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस के अवसर पर भारत की सबसे बड़ी एल्युमिनियम निर्माता कंपनी, वेदांता एल्युमिनियम ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी कर्मचारी-नेतृत्व वाली सामाजिक पहल की घोषणा की। इसके तहत कंपनी के 1,800 कर्मचारियों ने मिलकर 4,000 घंटे से अधिक समय समुदाय की सेवा में दिया, जिससे ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के 7 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ मिला।

यह पहल 'सामुदायिक विकास' के प्रति कंपनी की सोच को दिखाती है जो वेदांता एल्युमिनियम की कार्य-संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कर्मचारी सिर्फअपने काम तक सीमित नहीं रहते, बल्कि सामाजिक कार्य में भी सक्रिय रूप से योगदान देते हैं।



वेदांता एल्युमिनियम अपने कर्मचारियों को स्वेच्छ से सेवा करने के लिए लगातार प्रेरित करती है। कर्मचारियों ने अपने कार्यस्थल से आगे बढ़कर स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, पर्यावरण और महिलाओं के सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में कई बदलाव लाने वाली गतिविधियों का नेतृत्व किया। इसमें पेड़ लगाने,

तालाबों की सफ़ाई, बच्चों को पढ़ाना, युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण, के लिए लगातार प्रेरित करती है। कर्मचारियों ने अपने कार्यस्थल से आगे बढ़कर स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, पर्यावरण और महिलाओं के सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में कई बदलाव लाने वाली गतिविधियों का नेतृत्व किया। इसमें पेड़ लगाने,

वेदांता एल्युमिनियम के सीईओ श्री राजीव कुमार ने कहा कि वेदांता एल्युमिनियम में हमारी जिम्मेदारी

केवल अपने प्रचालन तक सीमित नहीं है, बल्कि उन समुदाय तक भी है जहाँ हम काम करते हैं। अपने प्रचालन क्षेत्र के आसपास हमारा प्रयास रहता है कि हम वहाँ सकारात्मक और स्थायी बदलाव ला सकें। इस वर्ष हमारे कर्मचारियों और सहयोगियों ने बड़े स्तर पर सेवा कार्यों में भाग लिया है।

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत अधिसूचित खरीफएवं रबी दलहनी-तिलहनी फसलों का जिले के जटगा एवं कोरबी समिति में होगी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन

कोरबा। जिले के किसान भी अपनी दलहन-तिलहन फसलों को प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान ुद्धौभद्र के अंतर्गत प्राईस सपोर्ट स्कीम के तहत अरहर, उड़द, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, चना, मसूर, एवं सरसों का क्रियर आदिम जाति सहकारी समिति के माध्यम से कर सकेंगे। जिस हेतु पात्र इच्छुक किसान अपना पंजीयन ‘‘एकीकृत किसान पोर्टल’’ के माध्यम से 01 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक करा सकते है।

उपार्जन की अवधि मूंग, उड़द, मूंगफली एवं सोयाबीन हेतु 01 दिसंबर 2025 28 फरवरी 2026 तक, अरहर एवं सरसों के लिए 15 फरवरी 2026 से 15 मई 2026 तक तथा चना एवं मसूर के लिए 01 मार्च 2026 से 30 मई 2026 तक आदिम जाति सेवा सहकारी समिति जटगा एवं कोरबी (पोड़ीउपरोड़ा) में किया जाएगा। उपार्जन हेतु फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (रु./क्विं.)



इस प्रकार है:- अरहर-8,000, मूंग-8768, उड़द-7800, मूंगफली-7263, सोयाबीन-5328, चना-5875, मसूर-7000, एवं सरसों-6200 निर्धारित है। ध्यान रहें एकीकृत किसान पोर्टलमें पंजीकृत कुषकों से ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी किया जायेगा। पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज-किसान का मोबाईल नंबर, आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका/बी-1 है। अधिक जानकारी हेतु कुषक अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी/वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी/अधिसूचित आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के समिति प्रबंधक से संपर्क कर सकते हैं।

धान खरीदी केन्द्र रक्शा में किसानों के आसानी से कट रहा है टोकन

सारांगढ़ बिलाईगढ़। खरीफविपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य चल रहा है। सेवा सहकारी समिति कोसीर के उप धान खरीदी केन्द्र रक्शा में कुल 848 किसान पंजीकृत है जिसमें से लगभग 200 किसानों के द्वारा 06 दिसंबर तक कुल 7215 क्विंटल धान विक्रय किया जा चुका है तथा आगामी दिवसों में धान खरीदी के लिये 169 किसानों के द्वारा



टोकन कटा लिया गया है।धान खरीदी की व्यवस्था को सुचारु रुप से संचालित करने के लिए छग. शासन के द्वारा किसानों का टोकन काटने के लिये ऑनलाईन एप्प टोकन तुहर हाथ के माध्यम से टोकन काटा जा रहा है तथा समिति में भी आकर किसान द्वारा टोकन कटवाया जा सकता है। इस प्रकार धान खरीदी केन्द्र रक्शा के किसानों को टोकन काटने में कोई समस्या नहीं है। किसानों का टोकन आसानी से कट रहा है तथा किसानगण खुश है। धान खरीदी केन्द्र रक्शा के पंजीकृत किसान रामेश्वर साहू ने बताया कि उनका टोकन कट गया है तथा टोकन काटने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुआ है। इसी प्रकार किसान योगेश लहरे ने बताया कि उनका टोकन कट गया तथा किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुई है।कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे के निर्देशन में सारांगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सभी धान खरीदी केन्द्रों में जिला प्रशासन के द्वारा सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की गई है,

इंडिगों विमान के परिचालन में रूकावट का असर, बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिल, पांचवे दिन की उड़ाने आज भी प्रभावित

जानकारी के अनुसार आज भी रायपुर में फ्लाइट शेड्यूल पूरी तरह गड़बड़ाया हुआ है।

रायपुर। इंडिगो विमान परिचालन में रूकावट का असर रायपुर के स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी देखने को मिल रहा है। आज इस रूकावट का पांचवा दिन है और आज भी रायपुर के माना एयरपोर्ट से दीगर शहरों के लिए उड़ान भरने वाली और आने वाली फ्लाइट कैंसिल है। जानकारी के अनुसार आज भी रायपुर में फ्लाइट शेड्यूल पूरी तरह गड़बड़ाया हुआ है।

नागर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू ने मंत्रालय के अधिकारियों और इंडिगो के सीईओ अल्बर्स के साथ स्थिति से निपटने को लेकर समीक्षा बैठक की। इंडिगो के उड़ान संचालन ठप होने के कारण यात्री लगातार पांचवे दिन फंसे हुए हैं।

मोपाल में भी उड़ाने प्रभावित

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तो यहां भी परिचालन में आंशिक सुधार देखा गया है।बावजूद परिचालन पूरी तरह बहाल नहीं हो पाया है। भोपाल से उड़ने



वाली दो फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। इनमें मुंबई और बेंगलुरु फ्लाइट शामिल है। दोनों ही उड़ाने ही 11.05 और 11:25 पर है। इसी तरह बेंगलुरु के लिए चल रही फ्लाइट में देर होने की बात कही जा रही है। यह फ्लाइट 8.50 की जगह 9.15 पर पहुंचेगी। इस तरह 13 में से 2 फ्लाइट आज प्रभावित है।

इंडिगो के सीईओ को शोर्कॉज नोटिस नागर विमानन महानिदेशालय-डीजीसीए ने इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर एल्बर्स और एकाउंटेबल मैनेजर इसीडो पोक्यूरूस को कारण

बताओ नोटिस जारी किया है और बड़े पैमाने पर उड़ाने रद्द होने को लेकर 24 घण्टे के अंदर जवाब देने को कहा है। उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को काफी असुविधा और परेशानी हुई।

‘इंडिगो के संसाधन प्रबंधन में बड़ी चूक’ : डीजीसीए

डीजीसीए ने इसके लिए स्वीकृत उड़ान समय सीमा मानदण्डों के तहत संशोधित जड़ुरतों के लिए पर्याप्त व्यवस्था न कर पाने के कारण हुए

[छत्तीसगढ़]

राष्ट्र की सुरक्षा में निरंतर तैनात हमारे सैन्य जवानों का योगदान अतुलनीय : मुख्यमंत्री

रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के सचिव ब्रिगेडियर विवेक शर्मा ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री श्री साय को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के प्रतीक स्वरूप सम्मान बैज लगाया तथा संचालनालय सैनिक कल्याण द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों एवं योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की।

मुख्यमंत्री ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सैनिकों एवं उनके परिवारों के कल्याण हेतु अपनी ओर से अंशदान भी प्रदान किया।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सशस्त्र

सेना झंडा दिवस हमारे वीर सैनिकों और उनके परिवारों के त्याग, साहस और राष्ट्रसमर्पण के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पावन अवसर है। देश की सुरक्षा में निरंतर तैनात हमारे जवानों का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने आगे कहा कि इस दिवस का संदेश है कि राष्ट्र की रक्षा में लगे हमारे जवानों और शहीद परिवारों के प्रति हम सभी अपनी जिम्मेदारी समझें और उनके कल्याण हेतु सहयोग की भावना से आगे आए।

मुख्यमंत्री ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सैनिकों एवं उनके परिवारों के कल्याण हेतु अपनी ओर से अंशदान भी प्रदान किया। इस अवसर पर सांसद श्री फगन सिंह कुलस्ते तथा पद्मश्री उषा बारले भी उपस्थित थीं।

रायपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो प्लाइट संकट बरकरार, मुंबई-0अहमदाबाद रूट की उड़ानें आज भी कैंसिल

है। इसके बाद केन्द्र ने यात्रियों की परेशानी कम करने के लिए सख्त कार्रया सीमा लागू कर दिया, तत्काल रिफंड का निर्देश दिया और किसी भी देरी के लिए कम्पनी पर कार्यवाई की चेतावनी दी। इंडिगो ने कल भी करीब 800 से अधिक उड़ानें रद्द की है।

रायपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो प्लाइट संकट बरकरार, मुंबई-0अहमदाबाद रूट की उड़ानें आज भी कैंसिल

रायपुर, 07 दिसंबर (आरएनएस)। छत्तीसढ़ की राजधानी रायपुर से इंडिगो प्लाइट क्राइसिस लगातार जारी है. शहर से इंडिगो की कुल 23 फ्लाइटें संचालित होती हैं, जिनमें से 5 फ्लाइटें अभी भी कैंसल हैं. फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.खास तौर पर मुंबई और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों की फ्लाइट्स अब भी कैंसल होने के कारण यात्रियों की यात्रा योजनाएं प्रभावित हो रही हैं. सरकार और एयरलाइन कंपनी स्थिति को जल्द सामान्य करने के प्रयास में लगी हुई है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से कुभकार समाज के प्रतिनिधि मंडल की सौजन्य मुलाकात

वन मंत्री के निर्देश पर तेंदुआ शिकार प्रकरण में त्वरित कार्रवाई, चार आरोपी गिरफ्तार

गिरफ्तार इन आरोपियों के पास से तेंदुए के कटे हुए चार पैर (नाखून सहित) बरामद किए गए

रायपुर। वन मंत्री केदार कश्यप के सख्त निर्देशों के बाद कांकर जिले में तेंदुआ शिकार प्रकरण पर वन विभाग ने तेज और प्रभावी कार्रवाई की। नरहरपुर परिक्षेत्र के देवी नवागांव के पास 4 दिसम्बर को एक नर तेंदुआ मृत अवस्था में मिला था। तेंदुए के चारों पैर कटे हुए पाए गए, जिससे अवैध शिकार और अंग तस्करी की आशंका की पुष्टि हुई। सूचना मिलते ही वन अमले ने मौके पर पहुंचकर कूप से तेंदुए के शव को बाहर निकाला तथा पशु चिकित्सकों की टीम से पोस्टमार्टम कराकर आवश्यक पंचनामा तैयार कराया गया। घटना को गंभीर मानते हुए अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध वन अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई।

वन मंत्री श्री कश्यप के निर्देशों के अनुरूप वरिष्ठ अधिकारियों मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) श्री जगलदेव मंडावी तथा वन संरक्षक राजेश कुमार चंदेल के



मार्गदर्शन में आरोपियों की सतत तलाश की गई। विभाग की विशेष टीम ने आज 6 दिसंबर को चार आरोपियों को गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। गिरफ्तार आरोपी में शखुदन पिता नारायण उम्र 51 वर्ष, श्रवण पिता महेंद्र उम्र 19 वर्ष, छबिलाल पिता बुदराम उम्र 35 वर्ष और बुदराम पिता अमरसिंह उम्र 71 वर्ष शामिल है। गिरफ्तार इन आरोपियों के पास से तेंदुए के कटे हुए चार पैर (नाखून सहित) बरामद किए गए। शिकार में उपयोग की गई

कुल्हाड़ी, रस्सी, लकड़ी आदि सामग्री भी जब्त की गई। पूरे प्रकरण को वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। जांच में ग्राम कोटवार, पटेल और स्थानीय ग्रामीणों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने टीम की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि वन्यजीवों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और अवैध शिकार में सलिस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

छग में कड़ाके की ठंड शुरू, बस्तर का न्युनतम तापमान 3 डिसी दर्ज

आगामी 72 घंटों में प्रदेश में शीतलहर चलने की संभावना

रायपुर । उत्तरी हवाओं का छग में प्रभाव पिछले 48 घंटों से दिखना शुरू हो गया है। प्रदेश में अब कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। रविवार सुबह बस्तर का न्युनतम तापमान 8.9 डिसी दर्ज किया गया। बदले मौसम के चलते आगामी 48 घंटों में बस्तर सरगुजा सहित संपूर्ण छग में शीतलहर चलने की संभावना आईएमडी एजेंसी ने व्यक्त की है। आईएमडी एजेंसी के अनुसार आज सुबह 8.30 बजे प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। सुबह सरगुजा में तापमान गिरकर 4.6 डिसी पर पहुंच गया है। प्रदेश के उत्तरी एवं मध्य भागों में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज होने से दो से 6 डिसी तापमान में कमी महसूस की गई है। प्रदेश में कोरिया जशपुर, बलरामपुर, सरगुजा में तापमान में तेजी से गिरावट होने के चलते ठिठुरन के साथ कड़ाके की ठंड का सामना क्षेत्रवासियों को करना पड़ रहा है। सरगुजा कोरिया एवं जशपुर में वहां के नगर पालिका प्रशासन द्वारा चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था भी की गई है।



आईएमडी के अनुसार उत्तरी पश्चिम दिशा आ रही शुष्क और ठंडी हवाओं के चलते आगामी 72 घंटों में तापमान और गिरावट दर्ज की जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित क्षेत्र के निवासियों से अत्यधिक ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनने की अपील करते हुए सिर्फ काम के समय ही घर से बाहर निकलने की अपील की है। इसके साथ ही देर रात तक घूमने वालों से भी स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से घर में रहने की सलाह दी गई है।

सझा खिलाने वाले आरोपी के कब्जे से 4नग सझा पर्ची एवं 3200 रुपया बरामद

जगदलपुर । एसपी बस्तर शलभ कुमार सिन्हा के निर्देश पर पुलिस के द्वारा अपराधिक तत्वों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। इसी तारतम्य शहर में सझा खिलाने वाले व्यक्ति पर बस्तर पुलिस की कार्यवाही करने में बस्तर पुलिस को सफ़्ताती मिली है। कोतवाली पुलिस को पेट्रोलिंग के दौरान सूचना मिला कि जमाल मिल के पीछे विनायक स्वामी नाम का व्यक्ति अवैध रूप से सझा जुआ खिलाया जा रहा है। सूचना पर मौके पर जाकर आरोपी विनायक स्वामी को हिरासत में 4 नग सझा पर्ची, 3200 रुपया नकदी के साथ पकड़ा। सझा खिलाने का वैध दस्तावेज नहीं होने पर विधिवत कार्यवाही किया गया।

एकीकृत किसान पोर्टल में किसानों के पंजीयन की तिथि बढ़ी

जशपुर । किसान हितों को ध्यान में रखते हुए एकीकृत किसान पोर्टल पर कैरीफरवर्ड, डूबान तथा वन पट्टाधारी कृषकों के पंजीयन हेतु निर्धारित समय सीमा बढ़ा दी गई है। विभाग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार अब यह प्रावधान 15 दिसम्बर 2025 तक सभी समितियों के समिति लॉगिन में उपलब्ध रहेगा। पूर्व में विभाग ने 30 नवम्बर 2025 तक इन प्रावधानों को समिति लॉगिन में उपलब्ध कराया था। किन्तु कैरीफरवर्ड, डूबान एवं वन पट्टाधारी कृषकों के पंजीयन की प्रक्रिया अभी जारी होने के कारण समय विस्तार आवश्यक पाया गया। इसलिए पंजीयन की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर 2025 तक बढ़ाया गया है। पंजीयन तिथि बढ़ने से छुटे हुए किसानों को सहूलियत होगी। साथ ही समितियों में धान बेचने में आसानी होगी। पूर्व में विभाग ने 30 नवम्बर 2025 तक इन प्रावधानों को समिति लॉगिन में उपलब्ध कराया था।

मार्कफेड ने जारी किए 1 नवंबर से 06 दिसम्बर तक के आंकड़े

रायपुर । छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारम्भ होने के पूर्व से ही प्रदेश में अवैध धान के भण्डारण एवं परिवहन से आने वाले धान की कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पिछले एक नवंबर से 6 दिसम्बर तक प्रदेश के विभिन्न जिलों से एक लाख 51 हजार 809 क्विंटल धान जब्त किया गया है। इस बार मार्कफेड द्वारा राज्य में अवैध परिवहन के जरिए अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ आने वाले धान को रोकने के लिए राज्य के सीमावर्ती जिलों में चेकपोस्ट और कलेक्टर की अध्यक्षता में टॉक्सफ़ेस भी बनाए गए हैं। इसके साथ ही मार्कफेड में स्थापित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था की सतत्



निगरानी की जा रही है। मार्कफेड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले एक नवंबर से 6 दिसम्बर के अवधि में मण्डी अधिनियम 1972 के तहत सीमावर्ती विभिन्न जिलों से छत्तीसगढ़ राज्य में अवैध परिवहन के माध्यम से आने वाले धान पर कार्यवाही की जा रही है। इनमें सर्वाधिक महासमुंद जिले में

25,718 क्विंटल धान जब्त किया गया है। इसी प्रकार धमतरी में 23,859 क्विंटल रायगढ़ जिले में 21,331 क्विंटल, राजनांदगांव 14,977 क्विंटल, बलरामपुर जिले में 9771 क्विंटल, बेमेतरा में 6490 क्विंटल, कवर्धा में 5734 क्विंटल, बालोद में 4595 क्विंटल, सारांगढ़-बिलाईगढ़ में 3770 क्विंटल, गौरैला-

पेंझ-मरवाही जिले में 2868 क्विंटल, जशपुर जिले में 2771 क्विंटल, सूरजपुर जिले में 2650 क्विंटल, दुर्ग में 2350 क्विंटल, जांजगीर-चांपा में 2014 क्विंटल, बलौदाबाजार में 1855 क्विंटल, बीजापुर जिले में 1842 क्विंटल, रायपुर में 1679 क्विंटल, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 1583 क्विंटल, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 1500 क्विंटल, बस्तर जिले में 1560 क्विंटल, मोहला-मानपुर-चौकी में 1402 क्विंटल, गरियाबंद में 1393 क्विंटल, कोरबा में 1346 क्विंटल, सरगुजा में 1282 क्विंटल, कोरिया में 1237 क्विंटल, सक्ती में 1201 क्विंटल, कोण्डागांव जिले में 1148 क्विंटल, बिलासपुर में 1060 क्विंटल, कांकर जिले में 1012 क्विंटल, मुगेली में 917 क्विंटल, दत्तेवाड़ा में 445 क्विंटल, नारायणपुर में 323 क्विंटल, सुकमा में 216 क्विंटल धान जब्त किए गए

शिशु मंदिर के मेधावी युवाओं ने भरी प्रशासनिक सेवा की उड़ान



रायपुर । प्रदेश के विभिन्न शिशु मंदिर विद्यालयों में अध्ययन कर पीएससी 2025 में सफलता प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों ने आज शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव से उनके रायपुर स्थित शासकीय निवास में सौजन्य भेंट की। मंत्री यादव ने सभी चयनित विद्यार्थियों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ दीं तथा प्रशासनिक सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने हेतु प्रेरित किया।नवा रायपुर स्थित आवास में आयोजित इस मुलाकात के दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिशु मंदिर संस्थान विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए शिक्षा के साथ संस्कार, राष्ट्रप्रेम और अनुशासन का अद्भुत समन्वय प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि यह शिक्षा पद्धति विद्यार्थियों को केवल परीक्षा में सफलता ही नहीं दिलाती, बल्कि उन्हें भविष्य में सशक्त समाज एवं राष्ट्र निर्माण में प्रभावी भूमिका निभाने योग्य भी बनाती है।मंत्री यादव ने आगे कहा कि माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार युवाओं को अवसर, प्रोत्साहन और संसाधन उपलब्ध कराने निरंतर प्रयासरत है।

प्रशासनिक सेवाओं में युवाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार शिक्षा, प्रशिक्षण एवं कौशल वृद्धि के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहलें कर रही है।कार्यक्रम में विद्या भारती प्रदेश संगठन मंत्री डॉ. देव नारायण साहू एवं विद्या भारती क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जुड़ावन सिंह ठाकुर की गरिमामयी उपस्थिति रही। दोनों वरिष्ठ पदाधिकारियों ने चयनित विद्यार्थियों को शुभकामनाएँ देते हुए राष्ट्रहित में सेवाभाव से कार्य करने का आग्रह किया।

‘टोकन तुंहर एप्प’ से किसानों को मिल रही है सहूलियत

रायपुर । राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का सिलसिला तेजी के साथ जारी हैं। पिछले माह के 14 नवंबर से शुरू हुए धान खरीदी महाअभियान में पांच दिसम्बर को सवरे 10 बजे जारी रिपोर्ट के अनुसार 22 लाख 39 हजार 433 लाख मीट्रिक टन से अधिक की धान की खरीदी हो चुकी है। अब तक 4 लाख 39 हजार 511 पंजीकृत किसानों ने धान बेचा है। धान खरीदी के एवज में किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत भुगतान हेतु मार्कफेड द्वारा 5277 करोड़ रूपए जारी किए गए है। चालू खरीफ सीजन के लिए इस वर्ष 27 लाख 30 हजार 96 किसानों ने पंजीयन कराया है, जिसमें 31 लाख 51 हजार 771 हेक्टेयर रकबा शामिल है। राज्य में सभी जिलों में धान खरीदी जारी है। धान खरीदी से अब तक महासमुंद जिला सर्वाधिक 15 लाख 19 हजार 650 क्विंटल धान खरीदकर पहले पायदान पर है। वहीं गरियाबंद जिले 6 लाख 73 हजार 495 क्विंटल धान खरीदकार दूसरे नम्बर पर है। इसी तरह बिलासपुर जिले 6 लाख 73 हजार 65 क्विंटल धान खरीदकर तीसरे स्थान हासिल की है। हालांकि कांकर जिला 6 लाख 15 हजार 431 क्विंटल धान खरीदी कर चौथे पायदान पर बने हुए है।